शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार में
मध्यप्रदेश

अनलॉक-1 • आज से कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर प्रदेश में बिना पास कहीं भी घूमें

8 जून से शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल खुलेंगे; स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे

इंदौर 60% तक खुल जाएगा, बाकी धीरे-धीरे खुलेगा

भास्कर न्यूज़ | भोपाल

मध्यप्रदेश सोमवार से अनलॉक होना शुरू हो जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार रात घोषणा की कि प्रदेश में अब रेड और ग्रीन जोन नहीं होंगे। सिर्फ कंटेनमेंट क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरा प्रदेश आवागमन, व्यापारिक गतिविधियों के लिए खुल जाएगा। राज्य के भीतर-बाहर बिना पास आ जा सकेंगे। कंटेनमेंट क्षेत्र में 30 जून तक लॉकडाउन रहेगा।

भोपाल, इंदौर, उज्जैन में नगर निगम सीमा के भीतर निजी व सरकारी दफ्तर (कंटेनमेंट को छोड़कर) 50%, जबकि शेष प्रदेश में 100% कर्मचारियों के साथ खुल सकेंगे। कर्मचारियों के भोजन के अवकाश का समय अलग-अलग होगा। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक बसें इंदौर, उज्जैन, भोपाल को छोड़कर बाकी संभागों में 50% क्षमता के साथ चलेंगी। अंतरराज्यीय बसें संचालन पर फैसला 7 जून के बाद होगा। सीएम ने कहा कि कोरोना पर काफी हद तक विजय पा ली है। फिर भी सावधानी जरूरी है। 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चे बिना स्वास्थ्य कारण के बाहर नहीं निकलें।

भोपाल, इंदौर में सभी दफ्तर 50% कर्मचारियों के साथ खुलेंगे, बाकी जगह 100%

• रेस्टोरेंट, होटल सब खुल जाएंगे

कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल, होटल, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे। लेकिन, प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा।

• स्कूल-कॉलेज पर फैसला जुलाई में

12वीं की परीक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि खोलने का फैसला सभी पक्षों की राय के बाद जुलाई में लिया जाएगा।

• इन पर प्रतिबंध जारी रहेगा

सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष, मैरिज गार्डन, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियां।

घरेलू बिजली बिल आधे हुए, उद्योग, दुकान शोरूम, रेस्त्रां से फिक्स चार्ज की वसूली टली

फिक्स चार्ज के लिए स्कीम... इस अक्टूबर से अगले साल मई तक 6 किश्तों में चुका सकेंगे

भास्कर न्यूज़ | भोपाल

लॉकडाउन में घरेलू उपभोक्ताओं को मिले बिजली के बिल अब आधे हो जाएंगे। दुकान, बड़े-छोटे उद्योग, शोरूम, अस्पताल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन, पार्लर आदि से अप्रैल से जून माह तक के बिजली बिलों पर फिक्स चार्ज फिलहाल नहीं लिया जाएगा। यह राशि अक्टूबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक छह समान किश्तों में बिना ब्याज के जमा की जा सकेगी।

मुख्यमंत्री ने रविवार को बिजली बिलों में बड़ी राहत देते हुए बताया कि इससे लगभग 12 लाख उपभोक्ताओं को लाभ होगा। फिक्स चार्ज वाली राशि करीब 700 करोड़ रुपए है। उपभोक्ता यदि अप्रैल और मई के बिलों का भुगतान तय तिथि पर करते हैं तो उन्हें 1 प्रतिशत अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो कि घरेलू के लिए अधिकतम 10,000 रुपए तथा उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए एक लाख रुपए तक होगी। सभी थ्री फेस उपभोक्ताओं को लॉकडाउन की अवधि में आवेदन देने के 7 दिन बाद से कॉन्ट्रैक्ट डिमांड में कमी की सुविधा दी गई थी। यह सुविधा लॉकडाउन समाप्त होने के 15 दिन बाद तक की अवधि के लिए लागू रहेगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि पोषण आहार महिला स्व सहायता समूहों से ही बनवाया जाएगा। यह सालाना 1400 करोड़ रुपए का काम है। गौरतलब है कि पिछली कमलनाथ सरकार ने महिला स्व सहायता समूहों के फेडरेशन जो पोषण आहार बना रहे थे, उनके संचालन का जिम्मा एमपी एग्रो को दे दिया था। साथ ही निजी कंपनियों के प्रवेश का रास्ता भी खोल दिया था। शिवराज की घोषणा के बाद यह तय हो गया कि पोषण आहार का काम स्व सहायता समूहों के हाथ में ही रहेगा। शेष | पेज 10 पर

घरेलू उपभोक्ताओं के बिल का भुगतान इस तरह होगा

अप्रैल 2020 में आए बिल	मई-जून, जुलाई में संभावित बिल	मई, जून, जुलाई में भुगतान योग्य राशि	लाभान्वित उपभोक्ताओं की संख्या तथा राशि (लगभग)
100 रु. तक तथा संबल के हितग्राही	100 रुपए तक तथा संबल के हितग्राही	50 रुपए प्रतिमाह	60 लाख (100 करोड़ रुपए)
100 रुपए तक	100 रुपए से 400 रुपए तक	100 रुपए प्रतिमाह	28 लाख (150 करोड़ रुपए)
100 रुपए से अधिक 400 रुपए	400 रुपए से अधिक	बिल की आधी राशि भुगतान करनी होगी (शेष आधी राशि का निर्णय बिल की जांच के बाद होगा)	08 लाख (200 करोड़ रुपए)

एमपी में अनलॉक 1.0 कंटेंनमेंट एरिया में 30 तक रहेगा लॉकडाउन

भोपाल, इंदौर और उज्जैन को छोड़कर पूरा प्रदेश अनलॉक

सौ फीसदी स्टाफ के साथ होगा काम, जुलाई में खुलेंगे स्कूल-कॉलेज और कोचिंग संस्थान

कहीं भी आ-जा सकेंगे लोग, आठ जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल-रेस्टोरेंट

नगर संवाददाता, भोपाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश में कहा है कि लॉकडाउन के चौथे चरण के समाप्त होने के बाद पांचवां चरण अनलॉक 1.0 चरण होगा। हम इसमें भारत सरकार की गाइड लाइन का पूरा पालन करेंगे। मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि जिलों में अधिक प्रभावित मोहल्ला, कॉलोनी इत्यादि क्षेत्र कंटेनमेंट एरिया होंगे। इनमें 30 जून, तक लॉकडाउन लागू रहेगा। कंटेनमेंट क्षेत्रों में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर 8 जून से धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थान पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां, अन्य सेवाएं तथा शॉपिंग मॉल खोले जाएंगे। रात्रिकालीन कर्फ्यू का समय अब रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक होगा। इस दौरान अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।

पास की अनिवार्यता समाप्त

राज्य में और राज्य के बाहर आने-जाने वाले वाहनों के लिए किसी प्रकार के पास की आवश्यकता नहीं होगी। पास चेकिंग की व्यवस्था सोमवार से समाप्त होगी। पूरे प्रदेश में अंतरराज्यीय बसों का संचालन 7 जून तक बंद रहेगा। इंदौर, उज्जैन तथा भोपाल संभाग सहित पूरे प्रदेश में फैक्टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के परिवहन के लिए बसें संचालित करने की अनुमति होगी। राज्य के अंदर सार्वजनिक परिवहन की बसें इंदौर, उज्जैन व भोपाल को छोड़कर अन्य सभी संभागों में 50% क्षमता के साथ संचालित हो सकेंगी।

इन पर रहेगी पूर्ण पाबंदी

सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, सभा कक्ष मैरिज गार्डन आदि। सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़ी सभाएं आदि गतिविधियां बंद रहेंगी।

यहां बारी-बारी से खुलेंगी दुकानें

इंदौर, उज्जैन, नीमच और बुरहानपुर के नगरीय क्षेत्रों के बाजारों की एक चौथाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। भोपाल के बाजारों की एक तिहाई दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं। देवास, खंडवा नगर निगम तथा धार एवं नीमच नगर पालिका क्षेत्र की आधी-आधी दुकानें बारी-बारी से खुलेंगीं, परंतु स्टैंड अलोन दुकानें व मोहल्ले की दुकानें इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी। इनके अलावा शेष प्रदेश में दुकानों के खुलने पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा।

तीस जून तक नहीं खुलेंगे स्कूल

मुख्यमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थाएं तीस जून तक बंद रहेंगी। परंतु 12वीं की परीक्षाओं के लिए विद्यालय खोले जाएंगे। बाद में स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि को खोलने का निर्णय सभी लोगों के साथ परामर्श कर जुलाई में लिया जाएगा।

प्रवासी मजदूर कमीशन बनेगा, बिना ब्याज छोटे व्यवसायियों को दस हजार तक ऋण

सीएम की घोषणाएं

- प्रवासी मजदूरों के कल्याण के लिए प्रवासी मजदूर कमीशन बनाया जाएगा। हर प्रवासी मजदूर को कार्य के लिए बाहर जाने से पहले कलेक्टर के पास रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा, जिससे वह जहां भी जाए उसका ध्यान रखा जा सके।
- महिला स्व-सहायता समूहों के लिए कम ब्याज पर ऋण दिलाने की योजना प्रारंभ की जाएगी।
- छोटे व्यवसायियों को बैंकों के माध्यम से 10 हजार तक का ऋण बिना गारंटी के दिलवाया जाएगा, जिसमें 7 प्रतिशत ब्याज सरकार देगी।
- चने में 2 प्रतिशत तक तिवड़ा होने पर उसकी समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा सकेगी।
- किसानों को गत वर्ष का फसल ऋण चुकाने की तिथि 31 मई के स्थान पर अब 30 जून होगी।
- शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 330 करोड़ रूपए की राशि तथा स्मार्ट सिटी योजना में 500 करोड़ की राशि जारी की जाएगी।
- आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की योजना तैयार कर शीघ्र ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाएगा।

कार्यस्थलों के लिए दिशा-निर्देश

सभी शासकीय और प्रायवेट कार्यालय इंदौर, उज्जैन और भोपाल नगर निगम क्षेत्र में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ और शेष प्रदेश में पूरी क्षमता से खोले जाएंगे।

ये सावधानियां होंगी जरूरी

सभी दुकानें, ग्राहकों के बीच शारीरिक दूरी सुनिश्चित करेंगी और एक समय में 5 से अधिक व्यक्तियों को दुकान मे प्रवेश की अनुमति नहीं देंगी। विवाह संबंधी समारोह में मेहमानों की संख्या 50 से अधिक नहीं। अंतिम संस्कार संबंधित कार्यक्रम में व्यक्तियों की संख्या 20 से अधिक नहीं।

प्रदेश में 30 जून तक लॉकडाउन...

स्कूल-कॉलेज रहेंगे बंद, मॉल्स और दुकानें 8 जून से खुलेंगी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

मप्र में लॉकडाउन 5.0 की अवधि को आगे बढ़ाकर 30 जून तक कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा कर दी। इसके तहत रात में 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा।

कोरोना संक्रमण के लिए घोषित कंटेनमेंट क्षेत्र से बाहर 8 जून से कई तरह की गतिविधियां शुरू की जाएगी। धार्मिक स्थलों मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च के साथ ही होटल, रेस्टोरेंट, आतिथ्य सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। शापिंग मॉल भी खुलेंगे। हालांकि शैक्षणिक गतिविधियां, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग आदि जून तक बंद रहेंगे। 12 वीं की परीक्षा के लिए स्कूलों को खोला जाएगा।

कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन रहेगा जारी

केंद्र सरकार की गाइडलाइन अनुसार अगला चरण एक जून से शुरू होगा। प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से आर्थिक गतिविधियां शुरू की जाएगी। कंटेनमेंट एरिया में लॉकडाउन 30 जून तक प्रभावी रहेगा। इन क्षेत्रों में अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी तरह की गतिविधिंया बंद रहेगी। उक्त क्षेत्रों को छोड़कर बाकी पूरा प्रदेश सामान्य रहेगा। स्कूलों को जुलाई में पालकों से विचार विमर्श के बाद खोला जाएगा।

लंबी प्रतीक्षा के बाद जारी एम्पलाई कोड से ढाई लाख अध्यापकों का वेतन उलझन में

आईएफएमआईएस कोड से वेतन का भुगतान दूर-दूर तक नहीं दिख रहा संभव

भोपाल(आरएनएन)। स्कूल शिक्षा विभाग ने अध्यापक संवर्ग से राज्य स्कूल शिक्षा सेवा में नियुक्त शिक्षक संवर्ग के लिए जारी ट्रेजरी एम्प्लाइज कोड मुसीबत का कारण बन रहे हैं। व्याप्त कमियों और स्पष्ट निर्देश न होने के कारण इसमें आई एफएमआईएस द्वारा वेतन भुगतान नहीं हो पा रहा है। इस खामी के कारण प्रदेश के लगभग ढाई लाख से अधिक लोक सेवकों को नुकसान उठाना पड़ रहा है।

तत्संबंध में राज्य शिक्षक संघ म प्र के प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव ने कहा है कि नवनियुक्त संवर्ग का ट्रेजरी एम्प्लाइज कोड जारी होना पिछले 2 वर्ष से लंबित था। जिसकी मांग संघ सदैव करता रहा है। विगत दिवस ये कोड नंबर जारी किए गए। ट्रेजरी एम्प्लाइज कोड जारी तो हुए पर उससे सही वेतन भुगतान किया ही नही जा सकता।अध्यापक से सरकारी बने नवीन शिक्षक संवर्ग को वर्तमान में सातवां वेतनमान मिल रहा है जबकि आईएफएमआईएस में छठवां वेतनमान ही दिखाई दे रहा है। ऐसे में सही वेतन भुगतान हो ही नही सकता। प्रांताध्यक्ष जगदीश यादव सहित जानकारों का मानना है कि जब तक सातवें वेतनमान का अनुमोदन न हो तब तक सातवां वेतन इस माध्यम से दिया ही नहीं जा सकता। अनुमोदन में लगभग 1 माह से अधिक का समय भी लगेगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह अनुमोदन कौन करेगा अभी विभाग द्वारा इस संबंध में ही कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।

तत्काल जारी कराएं कोड

जगदीश यादव के अनुसार सरकार और विभाग के आला अधिकारियों से इस संबंध में पत्राचार भी किया गया। इसमें मांग भी की की गई थी कि जिन शिक्षकों के ट्रेजरी एम्प्लाइज कोड जारी नहीं हुई उनके तत्काल जारी करवाए जाए। साथ ही सातवें वेतनमान के अनुमोदन की जिम्मेदारी तय की जाए। ताकि इस माह का वेतन पूर्वानुसार ही भुगतान किया जाए। आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने इस संबंध में कोई ध्यान नही दिया है।

कार्यालयों में सफाई की मांग

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है कि सरकारी कार्यालयों में सफाई के बेहतर प्रबंध बनाए जाएं। श्री तिवारी ने कहा है कि हाल ही में मंत्रालय में भी कोरोना पॉजिटिव निकला है। इसके पहले सतपुड़ा और विध्याचल भवन में भी कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इस कारण सरकार को तत्काल सफाई व्यवस्था के साथ-साथ सोशल डिस्टेंसिंग पर भी ध्यान देना होगा। प्रमोद तिवारी का कहना है कि सरकारी कार्यालयों में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को लेकर शासकीय कर्मचारी दहशत में आ गए हैं।

आयुष छात्रों ने ज्ञापन सौंपा

आयुष छात्रों की समस्याओं को लेकर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन द्वारा विभाग के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 4 सूत्री मांगों के निराकरण की मांग की। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ शशांक राय ने बताया कि यह समस्याएं लंबे समय से लंबित पड़ी हुई है लेकिन उनका निराकरण नहीं हो पा रहा है। इससे छात्र छात्राओं को बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। श्री राय के मुताबिक अधिकारियों ने भरोसा दिया है कि शीघ्र उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

अतिथि शिक्षकों ने मांगा सरकार से न्याय

प्रदेश के अतिथि शिक्षकों ने मौजूदा राज्य सरकार से न्याय देने की गुहार लगाई है। अतिथि शिक्षक संघ के अध्यक्ष सुनील परिहार का कहना है कि विभाग में उनकी लगातार उपेक्षा की जा रही है। सरकार का जो वचन ही उसके अनुसार लाभ नहीं मिल पा रहा है। मौजूदा समय में लॉक डाउन चल रहा है। इस समय एक प्रकार से पूरे प्रदेश के अतिथि शिक्षक घर पर बेरोजगार बैठे हुए हैं। उन्होंने मांग की है कि सरकार अतिथि शिक्षकों के स्थाई रोजगार की व्यवस्था करें।

बच्चों ने कविताओं के माध्यम से दिया जागरूकता संदेश

भोपाल। जवाहर बाल भवन द्वारा बच्चों को रचनात्मक कलाओ से जोड़े रखने के लिए विभिन्न कलाओं का ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी श्रंखला में रविवार को अरविन्द शर्मा के निर्देशन में सृजनात्मक लेखन प्रभाग के बच्चों के लिए बाल काव्य पाठ का आयोजन किया गया। जिसमें बाल कवि, विभोर, कबीर, शीर्ष, नंदनी, अस्तित्व, आदया, आयुष, प्रतिज्ञा एवं खुशी ने काव्य रचना प्रस्तुत की। बच्चों ने कोरोनाए उसके बचाव, घर लौटते मजदूर, कोरोना संकट में उत्पन्न हुए विशेष शब्दों, देश, मां विषयों पर आधारित रचनाओं का सस्वर पाठ किया। विभोर श्रीवास्तव ने कोरोना कैसी के महामारी है, आदया भारती ने मकान को घर बना दें, गुरुर को सेनेटाइज करा दें, प्रतिज्ञा सोनी ने हमारी हिम्मत देख पस्त हो जाएगा, कोरोना देश से भाग जाएगा, आयुष कठैत ने दूर रखना है कोरोना, शेक हैंड करो ना, खुशी सक्सेना ने रहा सहा बचपन छीनने, कोरोना आया हमारे बीच में, कबीर दुबे ने लॉकडाउन और रविवार, नन्दिनी बंसल ने छोटी-छोटी बातें, छोटे-छोटे उपाय अपनाओ, शीर्ष खरे ने मजदूरों की व्यथा एवं अस्तित्व शुक्ल ने मां को कुछ न बोलो अपनी मार्मिक रचना प्रस्तुत की।

दूसरे राज्यों के 50 हजार विद्यार्थियों की परीक्षा कराना मंडल के लिए चुनौती

शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव ने कहा कि हम जानकारी जुटा रहे

उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश से पूरी तरह अलग

भोपाल ■ गौरीशंकर चौरसिया

कोरोना आपदा के बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 12वीं के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा का टाइम टेबल तो बना दिया है लेकिन बोर्ड के समक्ष कई चुनौतियां मुंह खोल कर खड़ी हो गई है। मध्यप्रदेश तो ठीक दूसरे राज्य के लगभग 50 हजार विद्यार्थी भी इस आपदा के बीच अपने घरों की ओर प्रस्थान कर गए हैं। अब ऐसे छात्रों की परीक्षा कराना मंडल के लिए बड़े संकट का कारण बन गया है। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव का कहना है कि बाहरी राज्यों के छात्रों की विस्तृत जानकारी जुटाई जा रही है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर इसी सप्ताह माध्यमिक शिक्षा मंडल 12वीं के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा कराने का निर्णय लिया था। इसके लिए बाकायदा 9 जून से दो पारियों में परीक्षा कराने के लिए टाइम टेबल तैयार हुआ था। अब मंडल के समक्ष दूसरे राज्यों के छात्र चिंता का कारण बन रहे है। यह छात्र अपने राज्य से आकर मध्य प्रदेश के स्कूलों में अध्ययन कर रहे थे। हायर सेकेंडरी के शुरुआती विषयों परीक्षा भी इन्होंने यहीं से दी है। लोक डॉन के चलते अब यह छात्र अपने घरों की ओर लौट गए हैं। जानकारी है कि करीब 50ए000 ऐसे छात्र हैं जो बाहरी प्रदेशों से आकर मध्य प्रदेश के स्कूलों में 12वीं की पढ़ाई कर रहे थे। 1 मार्च से शुरू हुई हायर सेकंडरी की परीक्षा भी विद्यार्थियों ने यहीं से दी थी। लेकिन 9 जून से प्रारंभ होने वाली इम्तिहान में इन छात्रों का बैठना मुश्किल लग रहा है।

दूसरे राज्य का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश से अलग

मंडल ने मध्य प्रदेश के लिए तो नियम बनाया है कि जो छात्र जहां होगा वहीं परीक्षा दे सकता है। इसके लिए उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें भी तकनीकी अड़चन यह है कि राज्य में खासकर ग्रामीण अंचलों में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। इसलिए वहां पर ऑनलाइन आवेदन करना मुश्किल है। अबे यदि अन्य राज्यों की बात करें तो वहां का पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश से अलग हटकर है। उप्र, गुजरात, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों के विद्यार्थी मप्र के शासकीय और प्राइवेट स्कूलों में अध्ययन कर रहे थे। ऐसे अधिकांश छात्र मौजूदा समय में अपने पुश्तैनी घरों पर है। ऐसे हालातों में मंडल के समक्ष समस्या यह है कि इन छात्रों को मध्य प्रदेश कैसे बुलाया जाए। छात्र जहां है यदि वहां पर परीक्षा कराई जाती है तो दूसरे राज्यों का पाठ्यक्रम आड़े आ रहा है। इस संदर्भ में मंडल के जवाबदार अधिकारी बात करने से बचते रहे। मंडल सचिव एवं अतिरिक्त सचिव को फोन लगाया गया। इनमें से किसी ने भी मोबाइल रिसीव नहीं किया।

हमारी कोशिश, कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित ना हो: रश्मि अरुण शमी

इस संदर्भ में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी का कहना है कि

बाहरी राज्यों के कितने छात्र हायर सेकेंडरी में मध्य प्रदेश के स्कूलों से अध्ययन कर रहे थे। इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। हमारी कोशिश यही है कि कोई भी बच्चा परीक्षा से वंचित ना हो। विभाग का समुचित प्रयास है कि प्रत्येक विद्यार्थी को उसके साल भर की मेहनत का बेहतर परिणाम मिले। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में माध्यमिक शिक्षा मंडल तेजी से काम कर रहा है। विभाग प्रमुख सचिव का कहना है कि हमारा प्रयास विद्यार्थियों का उज्जवल भविष्य बनाने का है। जहां तक मध्यप्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पहुंचे छात्रों का है। तो उनकी समस्या समाधान के लिए भी बोर्ड मंथन कर रहा है।

ऑनलाइन पढ़ाई बच्चों के साथ अभिभावकों को टेक्नोलॉजी से जोड़ने का माध्यम

भोपाल। आपदा के बीच घरों में कैद बच्चों को मानसिक रूप से एकाग्रचित रखने हेतु शुरू हुआ ऑनलाइन अध्यापन नई क्रांति ला रहा है। यह सिस्टम बच्चों के साथ साथ उनके अभिभावकों को भी टेक्नोलॉजी से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहा है। इधर विभाग का कहना है कि बच्चों का सुनहरा भविष्य तैयार करना ही हमारा लक्ष्य है।बताना होगा कि लॉक डाउन होने के कारण इस समय बच्चे भी अपने घरों में कैद हैं। बच्चों का मन कहीं भटके ना इस कारण विभाग ने पिछले सप्ताह डीजे लैप ऐप के माध्यम से बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई प्रारंभ की थी। प्रदेश की भौगोलिक समस्याओं को समझते हुए विभाग ने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक साथ कई विकल्प चुने। इसके लिए मोबाइल दूरदर्शन और रेडियो को विकल्प बनाया गया। यदि जिन अभिभावकों के पास एंड्राइड मोबाइल है। तो वह अपने बच्चों को उसके माध्यम से विभाग द्वारा ऑनलाइन जारी की गई पाठ सामग्री का अध्ययन कर सकते है। जिन अभिभावकों के पास यह मोबाइल नहीं है तो वह टीवी पर दूरदर्शन चैनल देखकर या फिर रेडियो के माध्यम से भी सुनकर अध्ययन करवा सकते हैं। विभाग के इस कदम के सकारात्मक नतीजे भी सामने आ रहे हैं। छतरपुर जिला अंतर्गत डहरा गांव के निवासी रामप्रकाश गुप्ता के अनुसार विभाग का यह नया सिस्टम हमें भी नई तकनीक और जानकारी से जोड़ रहा है। बच्चों को पढ़ाने में हमारी जहां रुचि बढ़ रही है तो सीखने की भी एक ललक है। उन्होंने बताया है कि इससे मिल रहा नया ज्ञान सीखने की क्षमताओं का विकास कर रहा है। भोपाल निवासी मुंशी राम चौरसिया कहते हैं कि पोता पोती ओं की पढ़ाई पर वह खुद ध्यान देते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई कोई कठिन नहीं है सिर्फउसके प्रति झुकाव जरूरी है। मोबाइल पर जितना ज्यादा काम करेंगे उतना ही ज्यादा ज्ञान बढ़ता है। उन्होंने बताया कि आने वाला समय तकनीकी क्रांति का है इसलिए टेक्नोलॉजी का अधिक से अधिक ज्ञान लेना चाहिए। आसानी से ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है।

पढ़ाई के अच्छे नतीजे आए यही हमारा प्रयास

इस संबंध में स्कूल शिक्षा विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी का कहना है कि ऑनलाइन अध्यापन के अच्छे नतीजे आए। यही हमारा प्रयास है। इसके लिए क्रमवार जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा अधिकारियों बीआरसीसी और शिक्षकों को जवाबदारी सौंपी गई है। हमारी कोशिश यही है कि लॉकडाउन की अवधि में बच्चे कहीं भटके ना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। इस कारण हमने ऑनलाइन अध्यापन का मसौदा तैयार किया था। विभाग प्रमुख सचिव का कहना है कि हमारी कोशिश बेहतर से बेहतर बनाने की है।

अब कक्ष में पहले से ही रखे होंगे सेनिटाइज पेपर और कॉपियां

विद्यार्थियों को 50 मिनट पहले पहुंचना होगा केंद्र, मास्क-सेनिटाइजर साथ लाना जरूरी

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (आरजीपीवी) में 23 जून से परीक्षा शुरू होने वाली है। जिसे लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। छात्र-छात्राओं को परीक्षा केन्द्र पर निर्धारित समय से 50 मिनट पूर्व उपस्थित होना होगा। पहले यह समय 30 मिनट था। 20 मिनट की बढ़ोतरी इसलिए की गई, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के साथ विद्यार्थी परीक्षा कक्ष तक पहुंच सके। परीक्षार्थी द्वारा स्वयं के साथ प्रवेश पत्र, मास्क, सेनिटाइजर, पानी की बोतल तथा दवाइयां (यदि परीक्षार्थी पूर्व से उपयोग करता हो) ले जा सकेंगे। इस बार परीक्षा के समय एक और नई व्यवस्था भी की गई है। अब तक परीक्षार्थी के निर्धारित स्थान पर बैठने के बाद ही पेपर और कॉपी का वितरण होता था, लेकिन अब पहले से ही सेनिटाइज की हुई कॉपी और पेपर परीक्षार्थी के टेबल पर पहले से ही रखे होंगे। आरजीपीवी ने कहा है कि परीक्षा की सामग्री छात्र साथ लेकर जाएं तथा किसी अन्य छात्र से सामग्री बचाव के चलते न लें।

खास बातें

- आरजीपीवी ने परीक्षा को लेकर गाइडलाइन की जारी
- आरजीपी में 23 जून से शुरू होगी परीक्षा

सेंटरों की संख्या 120 से बढ़ाकर की 230

विवि ने इस बार छात्रों को परीक्षा फार्म भरने के साथ वर्तमान लोकेशन के अनुसार मध्य प्रदेश के भीतर निर्धारित परीक्षा केंद्र का चयन करने की सुविधा दी गई है। पहले परीक्षा केंद्रों की संख्या 120 थी, जिसे बढ़ाकर 230 कर दिया गया है। इस परीक्षा में 40 हजार छात्र शामिल होंगे। शनिवार तक विवि के पास करीब 13 हजार 500 आवेदन पहुंच चुके हैं। वर्तमान समय में प्रदेश से बाहर रह रहे छात्रों को भी मध्यप्रदेश में ही किसी निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर ही परीक्षा में सम्मिलित होना होगा।

मैनिट की ऑनलाइन परीक्षा आज से शुरू

मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (मैनिट) की आज 1 जून से ऑनलाइन परीक्षा शुरु हो रही है। प्रत्येक सब्जेक्ट के पेपर 30 अंक के होंगे। विद्यार्थी घर बैठकर मोबाइल, लैपटॉप या कम्प्यूटर से परीक्षा दे सकेगा। खास बात यह है कि ओपन बुक पेटर्न पर परीक्षा होने से विद्यार्थी बुक खोलकर भी प्रश्नों के जवाब दे सकेगा, हालांकि निर्धारित समय सीमा होने से उसे समय का विशेष ध्यान रखना होगा। प्रत्येक विषय में 100 नंबर के आधार पर अंक दिए जाएंगे। इसमें से ऑनलाइन एग्जाम (ओपन बुक पेटर्न) सिर्फ 30 अंकों का होगा। मिनी टेस्ट और असाइनमेंट के 10-10 अंक रहेंगे। यह विद्यार्थियों से पहले ही लिए जा चुके हैं। वहीं प्रीवियस सेमेस्टर के सीजीपीए के आधार पर 30 अंक का निर्धारण होगा। शेष 20 अंक वायवा के रहेंगे।

बीयू ने जारी किया यूजी तृतीय वर्ष और पीजी चतुर्थ सेमेस्टर का टाइम टेबल

बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय (बीयू) ने रविवार को यूजी तृतीय वर्ष और पीजी चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। बीएससी होम साइंस की परीक्षा 29 जून से 7 जुलाई तक, बीसीए की परीक्षा 29 जून से 4 जुलाई, बीएससी पार्ट की परीक्षा 29 जून से 18 जुलाई और बीकॉम ऑनर्स की परीक्षा 29 जून से 4 जुलाई के मध्य आयोजित होगी। इन सभी परीक्षा का समय सुबह 7 बजे से सुबह 10 बजे का रहेगा। इसके अलावा सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक बीबीए और बीकॉम की परीक्षा आयोजित होगी। यह परीक्षा भी 29 जून से 4 जुलाई के मध्य होगी। बीए की परीक्षा 29 जून से 17 जुलाई के मध्य दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी। इसी तरह एमएससी होम साइंस की परीक्षा 4 जुलाई से 8 जुलाई, एमए/एमएससी मैथमेटिक्स की परीक्षा 29 जून से 14 जुलाई, एमएससी की परीक्षा 4 जुलाई से 14 जुलाई, एमकॉम की परीक्षा 4 जुलाई से 8 जुलाई और एमए की परीक्षा 4 जुलाई से 13 जुलाई के मध्य होगी इन सभी परीक्षाओं का समय सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रहेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग सुरक्षा के साथ स्कूल खोलने की कर रहा तैयारी

जुलाई में बच्चों को स्कूल भेजने से 70% अभिभावकों ने किया इनकार

हरिभूमि न्यूज ▶▶ भोपाल

कोरोना संक्रमण और इस घातक वायरस की रोकथाम के लिए लागू किए गए लॉकडाउन में शैक्षणिक संस्थानों को बंद रखा गया है। ऐसे में कोरोना के साथ ही सोशल मीडिया पर कई बार ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं, जिनमें कभी कभी जुलाई तो कभी सितंबर में स्कूल फिर से खुलने की बात कही जाती है। ऐसे में अभिभावकों में एक भय का वातारण निर्मित हुआ है। जहां स्कूल शिक्षा विभाग परिस्थितियों को देखते हुए पूरी तैयारी और सुरक्षा के साथ स्कूल खोलने पर विचार कर रहा हैं, वहीं लगभग 70 फीसदी अभिभावक इसके लिए तैयार नहीं हैं। दरअसल, भोपाल के विभिन्न स्कूल ग्रुप्स में जब जुलाई में स्कूल रि-ओपनिंग की संभावना जताते हुए मैसेज डाला गया तो 70 फीसदी अभिभावकों ने इसे मूर्खतापूर्ण फैसला करार देते हुए बच्चों को स्कूल भेजने से साफ इनकार कर दिया। यहां तक कि कुछ ने कहा कि वह क्लास रिपीट कराने को तैयार हैं, लेकिन बच्चे को लेकर इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते।

क्लास रिपीट कराने को तैयार हैं, लेकिन बच्चों को लेकर इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते पालक

कुछ ने भरी हामी

हालांकि कुछ अभिभावकों ने बच्चों को स्कूल शुरू होते ही पूरी सेफ्टी के साथ भेजने की हामी भरी। बता दें, इन ग्रुप्स में टोटल 336 अभिभावक हैं, जिनके बच्चे अलग-अलग क्लासेस और स्कूलों में हैं। हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में निर्णय लिया जाएगा।

बाल आयोग ने भेजी गाइडलाइन

बता दें कि मप्र बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी जुलाई की बजाए सितंबर से स्कूल खोले जाने के पक्ष में है। आयोग ने उसी वक्त के हिसाब से विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाने के लिए क्या-क्या सावधानियां बरतनी होंगी इसे लेकर विशेषज्ञों के साथ मिलकर एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तय की है और इस गाइडलाइन को स्कूल शिक्षा विभाग को भेजा है।

सितंबर तक तो न खोलें स्कूल

स्कूल कम से कम सितंबर तक तो नहीं खोले जाने चाहिए। अभी बुजुर्ग और बच्चों का सबसे अधिक ध्यान रखने की बात है। ऐसे में स्थितियां संभलने तक, स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं है।

पीयुष दीक्षित, अभिभावक

बच्चों को खतरा

अभी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, यह स्कूल खोलने से बेहतर विकल्प है। कम से कम इस साल स्कूल को यही करना चाहिए। अभी बच्चों की स्कूल में मैदरिंग खतरनाक साबित हो सकती है।

कंचन रघुवंशी, पालक

बदलनी पड़ेगी आदतें

कम से कम सितंबर तक तो स्कूल को नहीं खोलना चाहिए। अभी बच्चों को बहुत प्रिपेयर करना होगा। मास्क पहनना बड़ों के बस की बात नहीं, तो बच्चों का क्या। बच्चों को बहुत सारी आदतें बदलना पड़ेगी।

दिव्या गांधी, पालक

स्कूल भेजने की हिम्मत नहीं

जब सरकार लॉकडाउन हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही तो हम बच्चों को स्कूल भेजने की हिम्मत कैसे जुटा लें। इन स्थितियों में मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता यदि मेरे दोनों बच्चों का यह साल रिपीट भी हो तो।

अरविंद श्रीवास्तव, पालक

मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने तैयार की गाइडलाइन

प्रायमरी के बच्चों को न बुलाएं स्कूल, सितंबर से लगाएं कक्षा 6वीं से 12वीं तक की कक्षाएं

स्टार समाचार | भोपाल

पहली से पांचवीं कक्षा के बच्चों को जब तक कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, तब तक उनकी कक्षाएं नहीं लगाई जाएं। वहीं छठवीं से बारहवीं तक की कक्षाएं सितंबर से शुरू की जाएं। प्रायमरी कक्षाओं की पढ़ाई ऑनलाइन ही पूरी कराई जाए। स्कूलों में प्रत्येक कक्षा में 30 फीसदी बच्चों को दो दिन गैप कर बुलाया जाए। उन्हें होमवर्क ज्यादा से ज्यादा दिया जाए। वहीं अभिभावकों को अपने बच्चे का स्वस्थ होने का घोषणा पत्र देना है।

कुछ इस तरह के गाइडलाइन मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए तैयार किया है। इसे आयोग ने स्कूल शिक्षा विभाग को सौंपाकर पालन कराने की अनुशंसा की है। आयोग ने स्कूल प्रबंधन, शिक्षक, यातायात, बच्चे और अभिभावक सभी के लिए गाइडलाइन तैयार की है।

स्कूलों में जागरूकता एवं बचाव समिति का गठन हो

स्कूलों में कोविड-19 संक्रमण जागरूकता एवं बचाव समिति का गठन किया जाए। इसमें शिक्षक एवं विद्यार्थी को शामिल किया जाए। और इसकी सूचना जिला शिक्षा अधिकारी को भी दें। सूचना पटल पर समिति के सदस्यों के नाम चस्पा किया जाए।

स्कूल प्रशासन के लिए कार्यप्रणाली

- स्कूल को सैनिटाइज किया जाए।
- पीने का पानी व हाथ धोने का पानी की समुचित व्यवस्था हो।
- प्रत्येक कालखंड के बाद हाथ धोने की व्यवस्था हो।
- बच्चों के बीच बैठने की छह फीट की दूरी हो।
- विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से संबंधित जागरूक करें।
- स्कूल का शौचालय साफ-सुथरा हो, जिसकी सफाई दो-तीन बार होनी चाहिए।
- यूनिफार्म, जूते-मोजे अनिवार्य नहीं होना चाहिए, जिससे विद्यार्थी धुले कपड़े एवं सामान्य जूते-चप्पल पहनकर उपस्थित हो सके।
- महत्वपूर्ण विषयों की पढ़ाई स्कूल में हो, अन्य विषय क होमवर्क दें।

एनआईओएसः 10वीं, 12वीं की परीक्षा 17 जुलाई से

नई दिल्ली | राष्ट्रीय ओपन स्कूलिंग संस्था (एनआईओएस) ने 10वीं, 12वीं बोर्ड की परीक्षा की नई तारीखें घोषित की हैं। केंद्रीय मंत्री डॉ रमेश पोखरियाल ने बताया कि दोनों परीक्षाएं 17 जुलाई से शुरू होंगी और 13 अगस्त तक चलेंगी। 12वीं के 41 और 10वीं के 46 पेपर होंगे। परीक्षा दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगी।

भर्ती प्रक्रिया शुरू होने को लेकर असमंजस इंतजार में भावी शिक्षक

भोपाल। शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे प्रदेश के सरकारी स्कूलों के लिए इस सत्र की शुरुआत तक नए शिक्षकों की भर्ती खटाई में पड़ती नजर आ रही है। स्थाई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू होने को लेकर अभी भी असमंजस बरकरार है। वहीं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का जारी विज्ञप्ति में संशोधन एवं रिक्त पदों में वृद्धि की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर आंदोलन जारी है। परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी रंजीत गौर का कहना है कि मप्र शिक्षक पात्रता परीक्षा उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति व प्राविधिक सूची भी जारी कर दी गई थी। लेकिन भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है।

बीयू ने एक महीने पहले जारी किया परीक्षाओं का टाइम टेबल, सवा लाख छात्र देंगे परीक्षा

29 जून से होंगे बीयू के यूजी-पीजी फाइनल ईयर एग्जाम

नगर संवाददाता, भोपाल

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय ने यूजी-पीजी फाइनल ईयर की परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी कर दिया है। यह एग्जाम 29 जून से होंगे, जो 18 जुलाई तक चलेंगे। परीक्षाएं दो शिफ्टों में होंगी। पहले पाली के एग्जाम सुबह 7 से 10 और दूसरी पाली के एग्जाम सुबह 11 से 2 बजे तक होंगे। वहीं बीए फाइनल ईयर के एग्जाम दोपहर 3 से 6 बजे तक होंगे। बीयू ने परीक्षाओं का टाइम टेबल करीब एक महीने पहले जारी कर दिया है। टाइम टेबल की जानकारी छात्रों को भी दी जा रही है। विश्वविद्यालय का तर्क है कि इससे लॉकडाउन की वजह से जो छात्र घर जा चुके हैं, वे भी आसानी से परीक्षा शुरू होने से पहले आ सकेंगे। इससे किसी भी छात्र को परेशानी नहीं होंगी। वहीं बीयू का दावा कि 29 जून से होने वाले ये एग्जाम पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कराए जाएंगे। इसके लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। पहले ये परीक्षा 104 परीक्षा केंद्रों पर हो रहीं थीं। अब एग्जाम के लिए 50 और परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे। परीक्षाओं में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न हो, इसको देखते हुए अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इन परीक्षाओं में करीब सवा लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। इन परीक्षाओं के बाद फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम होंगे। बीयू के रजिस्ट्रार डॉ. बी भारती का कहना है कि छात्र आसानी से परीक्षा देने आ सकें, इसको देखते हुए एक महीने पहले परीक्षाओं का टाइम टेबल जारी किया गया है।

मैनिट के ऑनलाइन एग्जाम आज से

मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान फाइनल ईयर के एग्जाम 1 जून से कराने जा रहा है। यह एग्जाम पूरी तरह से ऑनलाइन होंगे। खास बात यह भी है कि इस ऑनलाइन परीक्षा में किताबों पर आधारित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में ऐसे सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें छात्रों को लॉजिक लगाना होगा।

आरजीपीवी की ऑफलाइन परीक्षा 23 से

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर एग्जाम 23 जून से शुरू होंगे। इन परीक्षाओं में छात्र अपनी सुविधा अनुसार परीक्षा केंद्रों का चयन कर सकते हैं। इससे दूर-दराज के जिलों में रहने वाले छात्रों को परेशानी नहीं होगी। वे उनके आसपास के शहर को परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। परीक्षा केंद्रों पर छात्रों को 50 मिनट पहले पहुंचना होगा। परीक्षा केंद्र पर बैठक व्यवस्था से आधे छात्र ही परीक्षा देंगे। इसके चलते विश्वविद्यालय ने परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ा दी है।

स्कूलों की नवीन मान्यता के लिए दस जून तक होंगे आवेदन

भोपाल, शप्र। कोरोना वायरस के चलते अब नवीन मान्यता के लिए प्रायवेट स्कूल दस जून तक आवेदन कर सकते है। यह मान्यता 2020-21 के लिए दी जाएगी। जबकि 2021-22 की नवीन मान्यता के लिए तीस जून तक की तिथि रहेगी। प्रदेश सरकार ने तीन माह पहले दसवीं-बारहवीं तक नए स्कूल खोलने के लिए नियम जारी किए हैं। पुराने स्कूलों की मान्यता नवीनीकरण पूर्व के मापदंडों के अनुसार की जाना थी। जबकि दसवीं-बारहवीं तक नए स्कूल खोलने के लिए एक एकड़ जमीन न्यूनतम होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूलों में लायब्रेरी, प्रशिक्षण शिक्षकों का स्टाफ, पर्याप्त टायलेट, कंप्यूटर कक्ष, खेल मैदान समेत अन्य व्यवस्थाएं होना चाहिए। प्राचार्य व स्टाफ के लिए कक्ष व प्रति विद्यार्थी दस वर्ग फीट बैठने के लिए स्थान व पांच वर्ग फीट खेलने के लिए होना चाहिए। पूर्व में नवीन मान्यता के लिए मई तक की तिथि थी। लॉकडाउन की अवधि बढ़ने के कारण नवीन मान्यता 2020-21 के लिए अब दस जून तक आवेदन कर सकते है। आवेदन के बाद 20 जून तक भौतिक सत्यापन,30 जून तक संभागीय जेडी नवीन मान्यता जारी करेंगे। जेडी कार्यालय से मान्यता निरस्त होने पर 10 जुलाई तक आयुक्त लोक शिक्षण में आवेदन कर सकते है। 28 जुलाई तक आयुक्त लोक शिक्षण प्रकरणों का निराकरण करेंगे। मान्यता मिलने के बाद 5 अगस्त के पहले माशिमं द्वारा संबद्धता दी जाएगी। वहीं, 2021-22 की मान्यता के लिए तीस जून तक आनलाइन आवेदन कर सकते है।

यूजीसी की स्कीम पर लॉकडाउन का असर, कई गतिविधियां होंगी प्रभावित

जागरण सिटी रिपोर्टर। कोरोना की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण हर सेक्टर प्रभावित हो रहा है और शिक्षा जगत भी इससे अछूता नहीं रहने वाला है। कोरोना लॉकडाउन से बिगड़ी आर्थिक स्थिति का असर अब विश्वविद्यालयों-कॉलेज पर पड़ सकता है। यूजीसी अनुदानित शैक्षिक, शोध और संसाधन विकास से जुड़ी योजनाओं के बजट में कटौती होने के आसार हैं। बजट और योजनाओं में तब्दीली भी हो सकती है।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) और अन्य योजनाओं में यूजीसी देश के सभी केंद्रीय, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों और कॉलेज को बजट देता है। इसके तहत संस्थानों में प्रयोगशाला के उन्नयन, स्मार्ट क्लास, कम्प्यूटर लेब, विद्यार्थियों के लिए फर्नीचर, आवश्यक संसाधन, केमिकल्स खरीदे जाते हैं। विश्वविद्यालयों-कॉलेज की शैक्षिक, शोध और विकास योजनाओं के अनुरूप यूजीसी बजट स्वीकृति देता है।

लॉकडाउन से बिगड़ा गणित

कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन से केंद्र और राज्य सरकारों का गणित गड़बड़ा चुका है। हालांकि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने 20 लाख 97 हजार करोड़ देने का ऐलान किया है। लेकिन मानव संसाधन विकास मंत्रालय-यूजीसी, केंद्रीय और राज्य स्तरीय शिक्षण संस्थानों को कितना बजट मिलेगा इसको लेकर खुलासा नहीं हुआ है।

किस्तों में मिलती है राशि

केंद्रीय और राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों-कॉलेज को शोध, संसाधनों के विकास और रूसा में बजट मिलता है। यह राशि किश्तों में दी जाती है। संस्थानों की योजनाओं और आवश्यकतानुसार बजट 5 से करीब 50 करोड़ और इससे अधिक भी होता है।

यह गतिविधियां हो सकती हैं प्रभावित

- साल या दो साल टल सकते हैं नए प्रोजेक्ट
- संस्थानों में नई शोध-अकादमिक योजनाएं बनाने पर रोक
- संस्थानों के बजट और योजनाओं में तब्दीली सम्भव
- केवल अहम शोध अथवा अकादमिक गतिविधियों के लिए बजट
- पूर्व में आवंटित/स्वीकृत बजट से चलाना पड़ सकता है काम

डिजिलेप से जुड़े हाईस्कूल और हायर सेकंडरी के 65 फीसदी स्टूडेंट

भास्कर न्यूज़ | सतना

कोरोना काल में लॉकडाउन के बीच स्कूली बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने रखने के लिए लागू की गई डिजिटल लर्निंग इनहैन्समेंट प्रोग्राम (डिजिलेप) से जिले के हाईस्कूल और हायर सेकंडरी के जहां 65 फीसदी स्टूडेंटस को जोड़ने में कामयाबी मिली है, वहीं प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के महज 36 प्रतिशत छात्र-छात्राओं को जोड़ा जा सका है। सभी विद्यार्थी सरकारी स्कूलों के हैं। उल्लेनीय है, जिले के सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 से 12 वीं तक 71 हजार और पहली से आठवीं तक की कक्षाओं में 1 लाख 70 हजार स्टूडेंट रजिस्टर्ड हैं।

बच्चों को स्मार्ट फोन देने से बचते हैं ग्रामीण

लॉकडाउन के दौरान घर बैठे अध्ययन की सुविधा के मामले में डिजिलेप के अच्छा नतीजे सामने आ रहे हैं,वहीं कुछ व्यवहारिक समस्याएं भी हैं। मसलन- ज्यादातर ग्रामीण अपने बच्चों को स्मार्ट फोन देने से बच रहे हैं,उन्हें यह पसंद नहीं कि बच्चे के पास 2 या 3 घंटे स्मार्ट फोन रहे। डीईओ ने बताया कि इस संबंध में ग्रामीण अभिभावकों को जागरुक बनाने के प्रयास चल रहे हैं। उन्हें डिजिलेप के महत्व की जानकारी दी जा रही है। इसी बीच एक तकनीकी बाधा ये भी है कि ग्रामीण क्षेत्र के ज्यादातर अभिभावकों के पास या तो स्मार्ट फोन नहीं हैं या फिर डाटा और नेटवर्क की समस्या है।

कमिश्नर ने दी फीड बैक लेने की हिदायत

इसी बीच रीवा संभाग के कमिश्नर डा.अशोक भार्गव ने संभाग के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को डिजिलेप की निरंतर मॉनीटरिंग और फीड बैक लेने की हिदायत दी है। उन्होंने शिक्षकों को कम से कम एक दिन में 5 अभिभावकों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए हैं। ऑन लाइन पढ़ाई का अभियान अप्रैल माह से चल रहा है। कमिश्नर ने टेलीफोन काल रजिस्टर बनाने, जूम वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा करने, डीईओ- डाइट प्राचार्य और संकुल प्रभारियों को वेबनार से जिला स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए हैं।

उत्कृष्ट प्रदर्शन पर होगा सम्मान

कमिश्नर ने डिजिलेप को और अधिक प्रभावी बनाए जाने की जरुरत जताते हुए कहा कि इसमें आ रही बाधाओं को प्राथमिकता के साथ दूर किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्कृष्ट कार्य करने पर संबंधितों को समारोह पूर्वक आयोजित कार्यक्रम में डिजिचैम्प प्रमाण-पत्र से सम्मानित किया जाएगा। उल्लेखनीय है, लॉकडाउन के दौरान बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखने के लिए डिजिलेप के तहत वाटसएप ग्रुप, दूरदर्शन और रेडियो प्रसारण के माध्यम को अपनाया गया है। स्टडी मैटेरियल राज्य शिक्षा केंद्र और लोक शिक्षण संचालनालय उपलब्ध कराते हैं।

डिजिलेप के अच्छे परिणामों के लिए ज्यादा से ज्यादा जागृति जरुरी है। फीडबैक से सुधार की संभावना बनती है। बाधाओं को दूर करने के लिए भी मानीटरिंग जरुरी है। उत्कृष्ट कार्य करने वालों को डिजिचैम्प प्रमाण-पत्र से समारोह पूर्वक सम्मानित किया जाएगा।

डा.अशोक भार्गव, कमिश्नर रीवा संभाग

डिजिलेप से अब तक जिले के हाईस्कूल और हायर सेकंडरी के 65 प्रतिशत तथा प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के 36 फीसदी विद्यार्थियों को जोड़ा जा सका है। अभिभावकों को जागरुक बनाने के प्रयास चल रहे हैं। अच्छे परिणाम की उम्मीद है।

टीपी सिंह, डीईओ सतना

अतिथि शिक्षक बोले- हमारे मुद्दे पर अब क्यों मौन हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया

भोपाल। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति ने पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधते हुए कहा कि वे जब कांग्रेस में थे तो नियमितिकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों के समर्थन में सड़कों पर उतरने की बात कर रहे थे। वहीं अब भाजपा में शामिल हो गये हैं तो उनके मुंह से आवाज नही निकल रही है। अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के प्रदेशध्यक्ष सुनिल सिंह परिहार ने कहा है कि टीकमगढ़ जिले के कुडीला गांव के कार्यक्रम में अतिथि शिक्षकों के हित में सड़कों पर उतरने की बात करने वाले महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया अब क्यों अतिथि शिक्षकों के मुद्दे पर मौन हैं। जबकि कांग्रेस की सरकार में अतिथि शिक्षकों की मांगे पूरी नहीं होने पर अतिथि शिक्षकों की ढाल और तलवार बनकर अतिथि शिक्षकों के हित में सड़कों पर उतरने की बात कही थी, और कांग्रेस की सरकार गिरा दी थी। अब भी आपकी ही सरकार है। उन्होंने मांग की है उप चुनाव से पहले अतिथि शिक्षकों के हित में निर्णय करवाकर मिसाल पेश करें, अथवा अतिथि शिक्षकों की मांगों को पूरा करने हमारे साथ बीजेपी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर जाएं। प्रदेश अध्यक्ष श्री परिहार ने बताया कि अतिथि शिक्षकों के समर्थन में अब तक लगभग पचास विधायक सरकार को पत्र लिख चुके हैं। इसी कड़ी में गुना विधायक गोपीलाल जाटव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।

स्कूल शिक्षा विभाग के दो अफसर सेवानिवृत्त

नगर संवाददाता | रीवा

शिक्षा विभाग के दो अधिकारियों को सेवानिवृत्त होने पर शनिवार को स्टॉफ द्वारा विदाई दी गई। संयुक्त संचालक कार्यालय में पदस्थ सहायक संचालक धीरेन्द्र सिंह एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रीवा के पद से विश्वात्मा खरे के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। विश्वात्मा खरे शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तण्ड क्रमांक-एक के प्राचार्य पद की जिम्मेदारी निभा रहे थे। संयुक्त संचालक अंजनी त्रिपाठी ने इस अवसर पर कहा कि शिक्षा विभाग की ये दोनों महत्वपूर्ण कड़ी रहे हैं। इनके अनुभवों का लाभ विभाग को मिलता रहा है।

इस दौरान जिला शिक्षा अधिकारी आरएन पटेल सहित अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसके बाद शिक्षक संघ की ओर से भी इन दोनों अधिकारियों को विदाई दी गई।

डिजिटल लर्निंग : प्रतिदिन पांच अभिभावकों से सम्पर्क करें शिक्षक

बारहवीं तक के सभी विद्यार्थियों को डिजिलेप अभियान से जोड़ें

नगर संवाददाता | रीवा

कोरोना संकट के कारण रीवा संभाग के सभी स्कूलों में नियमित कक्षायें बंद हैं, ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर देने के लिए शासन द्वारा डिजिटल लर्निंग इनहैन्समेंट प्रोग्राम डिजिलेप शुरू किया गया है। संभागायुक्त डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने जूम वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से डिजिलेप अभियान की समीक्षा की। बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को डिजिलेप अभियान से जोड़े जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा न आये। इसके लिए विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों से प्रत्येक शिक्षक मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करें। हर शिक्षक प्रतिदिन कम से कम पांच अभिभावकों से अनिवार्य रूप से संपर्क करें।

संभाग में सुधार की आवश्यकता

बैठक में अभियान की समीक्षा करते हुए डॉ. भार्गव ने कहा कि रीवा संभाग में डिजिलेप अभियान में अत्याधिक सुधार की आवश्यकता है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी डीपीसी सिंह, प्राचार्य डाइट तथा संकुल शिक्षक समय-समय पर आनलाइन बैठकें आयोजित कर डिजिलेप के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों को दूर करें। डिजिलेप कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को समारोह पूर्वक डिजिचैम्प प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा। बैठक में संयुक्त संचालक शिक्षा अंजनी कुमार त्रिपाठी, जिला शिक्षा अधिकारी आरएन पटेल, डीपीसी सुदामा पटेल तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से संभाग के अन्य जिलों के शिक्षा विभाग के अधिकारी तथा संकुल प्राचार्य शामिल रहे।

कवायद माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित करने की कर रहा तैयारी

10वीं का रिजल्ट जून में तो 12वीं का जुलाई में हो सकता है जारी

स्टार समाचार | भोपाल

मध्य प्रदेश का माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड रिजल्ट जून में घोषित करने की तैयारी कर रहा है। जून महीने के दूसरे हफ्ते में दसवीं कक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। वहीं 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जुलाई के महीने में घोषित किया जाएगा।

10वीं व 12वीं का रिजल्ट अलग-अलग होगा जारी

लॉक डाउन होने के चलते 10वीं और 12वीं के पेपर स्थगित हुए थे। दसवीं की स्थगित दो परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। वहीं कक्षा बारहवीं के स्थगित पेपर के लिए नई तारीखों का ऐलान किया गया है। दसवीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य भी लगभग पूरा होने पूरा होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी होने के बाद जून के दूसरे हफ्ते यानी 14 से 15 जून तक दसवीं का रिजल्ट घोषित किया जा सकता है। कक्षा 12वीं का रिजल्ट जुलाई के महीने में घोषित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है जब दोनों कक्षाओं का रिजल्ट अलग-अलग जारी किया जाएगा। 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में एक महीने या 15 दिन का अंतर रहेगा। इससे पहले दसवीं और बारहवीं का रिजल्ट एक साथ ही घोषित होता रहा है। हर जिले में लॉक डाउन से पहले ली गई परीक्षाओं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। कॉपियों के मूल्यांकन का कार्य 25 अप्रैल से शुरू किया गया था। 30 साल बाद शिक्षकों को घर पर ही कॉपियां चेक करने के लिए दी गई थी। उसके बाद परीक्षा केंद्रों पर डिप्टी वैल्यूवर की मौजूदगी में कॉपियों पर नंबर चढ़ाए गए हैं। कॉपियों का मूल्यांकन तीन चरणों में किया जाना है। 10वीं कक्षा की 70 फीसदी और 12वीं कक्षा की 30 फीसदी कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूरा हो चुका है। 10वीं और 12वी की एक करोड़ 33 लाख कॉपियों का मूल्यांकन पूरा किया जाना है।

साढ़े सात लाख से ज्यादा परीक्षार्थी होंगे शामिल

कक्षा बारहवी की स्थगित परीक्षाओं के के लिए नई तारीखों का ऐलान किया गया है। 9 जून से 16 जून तक कक्षा 12वी की परीक्षा ली जाएंगी। प्रदेश भर में 3657 परीक्षा केंद्रों पर करीब साढ़े सात लाख से ज्यादा परीक्षार्थी शामिल होंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षार्थियों के लिए यह सुविधा भी दी है कि जो भी परीक्षार्थी लॉक डाउन में जिस जिले में रह रहा है वह वहीं से उन नए परीक्षा केंद्रों से परीक्षा दे सकेंगे।

जो पेपर हुए उनके परफार्मेंस के आधार पर मिलेंगे नंबर

दसवीं के दो स्थगित पेपर अब नहीं लिए जाने का फैसला हुआ है। दो विषयों की स्थगित परीक्षाओं के ना लिए जाने से रिजल्ट घोषित करने में आसानी होगी क्योंकि दसवीं की कॉपियों का पहले से मूल्यांकन कार्य शुरू हो चुका है। 21 मार्च को स्थगित हुई परीक्षा के विषय में यह फैसला लिया गया है कि अब वे स्थगित पेपर नहीं लिए जाएंगे। जो परीक्षाएं रह गई थीं अब आयोजित नहीं की जाएंगी। दसवीं के जो पेपर हो चुके हैं उनकी परफॉर्मेंस यानी नंबर के आधार पर स्थगित विषयों में नंबर दे दिए जाएंगे और उनके नंबर के आधार पर ही रिजल्ट तैयार किया जाएगा। जो पेपर नहीं हो सके हैं उनके आगे पास लिखा जाएगा।

उत्तरपुस्तिकाओं के उपलब्ध होने में ही बीत जाएगा एक महीने का वक्त

29 जून से परीक्षा आयोजित करने की तैयारी कर रहा विवि

स्टार समाचार | रीवा/सतना

उच्च शिक्षा विभाग ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल सेमेस्टर की परीक्षाएं 29 जून से लेकर 31 जुलाई तक आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन इस कवायद में जुटा है कि 29 जून से परीक्षाएं प्रारंभ की जा सकें। गौरतलब है कि 29 जून को सिर्फ एक महीने का वक्त रह गया है। मगर विश्वविद्यालय में परीक्षा केन्द्रों का निर्धारण नहीं हो पाया है। यहां तक कि प्रश्न पत्र भी बनकर तैयार नहीं हैं और न ही उत्तरपुस्तिकाएं इस अवधि में विश्वविद्यालय को उपलब्ध हो पाएंगी। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं जुलाई के पहले पखवाड़े से प्रारंभ हो सकती हैं। जिन्हें आयोजित करने में भी विश्वविद्यालय को 20 दिन से ज्यादा का वक्त लग जाएगा। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर काफी सक्रियता बरत रहा है मगर विश्वविद्यालय का सिस्टम अधिकारियों की योजना पर हावी है। सबसे बड़ी समस्या की बात यह है कि जहां बाकी विश्वविद्यालयों के प्रश्न पत्र बनकर तैयार हो गए हैं वहीं अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र सेट नहीं हुए हैं। सूत्रों की मानें तो विश्वविद्यालय से जुड़े प्रोफेसर पेपर सेट करने के लिए राजी ही नहीं हो रहे हैं। इससे पहले विश्वविद्यालय ग्वालियर, जबलपुर की संस्थाओं के प्रोफेसर से प्रश्न पत्र सेट करवाता रहा है मगर उन प्रोफेसर्स से भी अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया। इसकी यह वजह भी बताई जा रही है कि वित्त विभाग की ओर से समय पर भुगतान न होने से भी लोग एपीएसयू का काम करने से कतरा रहे हैं।

परीक्षा फार्म का पोर्टल कब खुलेगा पता नहीं

डाटा मिलने के बाद उच्च शिक्षा विभाग लेगा निर्णय

ऐसी संभावना जताई जा रही है कि विश्वविद्यालय की परीक्षा आयोजित होते-होते जुलाई का पहला पखवाड़ा बीत जाएगा। हालांकि अधिकारी इसी कवायद में लगे हैं कि जल्द से जल्द परीक्षाएं आयोजित कराई जा सकें मगर परिस्थितियां योजनाओं के विपरीत जा रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने लीड कॉलेज को यह जिम्मेदारी दी है कि वह अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्धता रखने वाले सभी कॉलेजों से विद्यार्थियों का डाटा मांगे और केन्द्रों की उपलब्धता की जानकारी विश्वविद्यालय को भेजे। इसके बाद ही विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर कोई निर्णय सुना सकेगा। अब तक कॉलेजों ने लीड कॉलेज को जानकारी नहीं भेजी है।

6 तारीख तक होगा निविदा आमंत्रण

विश्वविद्यालय ने 75 लाख की उत्तरपुस्तिका के लिए निविदा आमंत्रण दिया है जो 6 जून तक वैध रहेगा। इसके बाद जो लोग टेण्डर फार्म भरेंगे, उनका चयन करने के लिए कमेटी बनेगी। उसके पश्चात क्रय आदेश की कमेटी बनेगी और तत्पश्चात एक संस्था को कॉपियां बनाने का टेण्डर पास किया जाएगा। आमतौर पर विश्वविद्यालय की सभी उत्तरपुस्तिकाएं तैयार करने में संविदाकार को 20 से 30 दिन का समय लग जाता है।

डिजिटल लर्निंग से होगी विद्यार्थियों की पढ़ाई

डिजिलेप अभियान युद्ध स्तर पर चलाएं : भार्गव

स्टार समाचार | सतना

कोरोना संकट के कारण रीवा संभाग के सभी स्कूलों में नियमित कक्षायें बंद हैं। ऐसी परिस्थिति में विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर देने के लिए शासन द्वारा डिजिटल लर्निंग इनहैन्समेंट प्रोग्राम डिजिलेप शुरू किया गया है। कमिश्नर डॉ. अशोक कुमार भार्गव ने जूम वीडियो कान्फ्रेंसिंग से डिजिलेप अभियान की समीक्षा की। कहा कि बच्चे हमारे राष्ट्र के भविष्य हैं। इनके ज्ञान का विस्तार, समय का सदुपयोग, आत्मविश्वास में वृद्धि, निर्णय लेने की क्षमता तथा तेजी से बदलती दुनिया से परिचित कराने के लिए शिक्षा नियमित हो। किसी भी स्थिति में शिक्षा प्रभावित न हो। कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण शिक्षण संस्थान प्रारंभ नहीं किये जा सकते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा डिजिलेप कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह विद्यार्थियों की गुणात्मक शिक्षा के विकास का महत्वपूर्ण आयाम है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी डिजिलेप अभियान को युद्ध स्तर पर चलायें। उन्हें डिजिटल लर्निंग से पढ़ाई का अवसर मिलेगा। भार्गव ने कहा कि कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को डिजिलेप अभियान से जोड़े जिससे उनकी पढ़ाई में बाधा न आये। इसके लिए विद्यार्थियों तथा उनके अभिभावकों से प्रत्येक शिक्षक मोबाइल फोन के माध्यम से संपर्क करें। हर शिक्षक प्रतिदिन कम से कम पांच अभिभावकों से अनिवार्य रूप से संपर्क करे।

विशेषकर उन अभिभावकों से जिनके पास व्हाट्सएप की सुविधा है किंतु वे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं। सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर तथा दीवार लेखन एवं अन्य माध्यमों से डिजिलेप अभियान का प्रचार-प्रसार करायें। प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्व सहायता समूहों के माध्यम से डिजिलेप अभियान के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करायें।

स्कूल शिक्षा विभाग अब नहीं कर सका कंटेनमेंट एरिया के 19 केंद्रों का फैसला

हरिभूमि न्यूज ▶▶| भोपाल

राजधानी के अलग-अलग कंटेनमेंट एरिया में आने वाले परीक्षा केंद्रों के बदलाव को लेकर पांच दिन बाद भी स्कूल शिक्षा विभाग कोई निर्णय नहीं ले सका है। विभागीय अधिकारियों द्वारा फिलहाल इन परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया है।

बता दें कि 9 जून से शुरू होने वाली परीक्षाएं अब 16 जून तक चलेंगी। दरअसल, स्कूल शिक्षा विभाग राजधानी के कंटेनमेंट एरिया में आने वाले 12वीं कक्षा के शेष पेपरों के लिए बनाए गए परीक्षा केंद्रों को एहितियात के तौर पर बदलने तैयारी कर रहा है। ऐसे 19 स्कूलों की सूची बनाई गई है जो कंटेनमेंट

केंद्रों को जांचा..

फिलहाल कंटेनमेंट एरिया में आने वाले परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया है। इस संबंध में निर्णय के लिए कलेक्टर सहित नोडल अधिकारी को लिखा जाएगा, जिसके बाद सेंटर को बदलने के संबंध में निर्णय हो सकेगा।

नितिन सक्सेना, जिला शिक्षा अधिकारी

ऑनलाईन पढ़ाई कर रहे खोरीबरी के आठ छात्र

निज संवाददाता-

पिपरई। जिले के कक्षा 9 वीं से लेकर 12 वीं तक के विद्यार्थियों को पूरे जिले में विद्यालयवार डिजीलेप ग्रुप बनाये गए हैं। जिसके माध्यम से शिक्षण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। जिले में कुल 9 से 12 तक के नामांकित छात्र 14116 हैं, जिनमें से एंड्राइड मोबाइल का उपयोग 5946 कर रहे हैं और 5189 विद्यार्थीगण सतत रूप से क्रियाशील रहकर लाभांवित हो रहे है। ग्राम खोरीवरी के छात्र मनीष अहिरवार ने बताया कि उसके घर डिजीलेप एप वाट्सप ग्रुप के माध्यम से विद्यालय के 8 साथी पढ़ाई कर रहे हैं।

10वीं का परिणाम जून में तो 12वीं का जुलाई में होगा जारी

भोपाल। माध्यमिक शिक्षा मंडल 10वीं बोर्ड का परिणाम जून माह में घोषित करने की तैयारी कर रहा है। जून महीने के दूसरे हफ्ते में दसवीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। वहीं 12वीं का परिणाम जुलाई माह में घोषित किया जाएगा। लॉकडाउन होने के चलते 10वीं और 12वीं के पेपर स्थगित हुए थे। दसवीं की स्थगित दो परीक्षाओं को निरस्त कर दिया गया है। वहीं कक्षा बारहवीं के स्थगित पेपर के लिए नई तारीखों का ऐलान किया गया है। दसवीं की कॉपियों का मूल्यांकन कार्य लगभग पूरा होने पूरा होने जा रहा है। माध्यमिक शिक्षा मंडल के सचिव का कहना है कि सारी तैयारियां पूरी होने के बाद जून के दूसरे हफ्ते यानी 14 से 15 जून तक दसवीं का परिणाम घोषित किया जा सकता है।

ट्राई ने नहीं की 11 अंकों के मोबाइल नं. की सिफारिश

नई दिल्ली, जेएनएन। टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (ट्राई) ने रविवार को स्पष्ट किया कि उनकी ओर से मोबाइल नंबर को 10 की जगह 11 अंकों का करने की सिफारिश नहीं की गई है। ट्राई ने कहा कि उसने 29 मई को फिक्स्ड और मोबाइल सेवाओं के लिए समुचित नंबरिंग संसाधन सुनिश्चित करने की सिफारिश की थी। मगर खबर यह फैल गई कि मोबाइल नंबर को 11 अंक का करने की सिफारिश की गई है। जबकि ऐसा कोई भी सुझाव नहीं दिया गया। हालांकि, देश के दूरसंचार नियामक ने यह सुझाव दिया है कि लैंड लाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए मोबाइल नंबर के पहले शून्य लगाना जरूरी किया जाना चाहिए। अभी फिक्स्ड लाइन से बिना शून्य लगाए भी मोबाइल पर कॉल किया जा सकता है। दरअसल, ट्राई का तर्क यह है कि डायलिंग पैटर्न में बदलाव करने से मोबाइल सर्विस के लिए 254 करोड़ नए नंबर बन सकेंगे।

जम्मू से लगभग 35 किमी दूर अखनूर जिले में चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान कॉलेज की लड़की स्वाति प्रवासी मजदूरों के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती हुई।

मां की प्यास बुझाएंगे

लॉकडाउन के कारण गर्मी के सीजन में प्याऊ नहीं खुल पाए लिहाजा राहगीरों को इस तरह से बुझानी पड़ रही है प्यास।

आर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावक निजी स्कूलों की नोटिस से परेशान

किताब के लिए पैसे नहीं और निजी स्कूल एंड्राइड मोबाइल खरीदने बना रहे दबाव

पत्रिका न्यूज पंच

कहा-ऑनलाइन पढ़ाई, शिक्षा कम व्यापार जादा, बंद कराए सरकार

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सतना. लॉकडाउन के कारण निजी स्कूलों का शिक्षा व्यापार बंद हुए तो संचालकों ने अभिभावकों से पैसा निकालने पढ़ाई का नया तरीका निकाल लिया। 20 मार्च से स्कूल बंद हैं। ऐसे में निजी विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर अभिभावकों पर फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई ने अर्थिक तंगी से जूझ रहे अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है।

कुछ निजी विद्यालय ऑनलान पढ़ाई की फीस जमा करने मैसेज भेज रहे हैं तो कुछ विद्यालय इसके बहाने किताब खरीदने का। हद तो यह है कि शहर के कुछ निजी स्कूल ऑनालइन पढ़ाई शुरू कराने अभिभावकों पर एंड्राइड मोबाइल खरीदने का दबाव बना रहे हैं। एक अभिभावक ने बताया कि हमारे पास बच्चे की किताब खरीदने के लिए पैसे नही हैं। ऐसे में हम ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 10 हजार का एंड्राइड मोबाइल कैसे खरीद सकते हैं।

पढ़ाई के नाम पर व्यापार ठीक नहीं: रिटायर्ड शिक्षक महेश गिरी का कहना है कि अप्रैल-मई छुट्टियों का सीजन होता है। जुलाई अगस्त में फिर से विद्यालय खुली जाएंगे। प्राइमरी के बच्चों का कोर्स पूरा कराने चार माह का समय पर्याप्त होता है। फिर निजी विद्यालय ऑनलाइन पढ़ाई पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं, समझ से परे हैं। अभिभावक राजेंद्र शर्मा का कहना है कि तीसरी क्लास का बच्चा ऑनलाइन क्या पढ़ेगा, यह सब को मालूम है। लेकिन समर्थ अभिभावक, जिनके पास कई एंड्राइड मोबाइल व घर में लैपटॉप हैं। वह ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार को कक्षा आठवीं तक ऑनलाइन पढ़ाई की इजाजत नही देनी चाहिए।

कोरोना भय के बीच परीक्षा का प्रेशर

जिले में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अभिभावक एवं छात्रों में कोरोना संक्रमण का भय बढ़ता जा रहा है। इस बीच माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9 से 15 जून के बीच 12वीं तक की बोर्ड परीक्षाएं कराने की घोषणा कर दी है। इससे अभिभावक परेशान हैं। मालिनी सिंह ने बताया कि उनका बेटा 12वीं में पढ़ता है। हमने उसे दो माह तक घर से नहीं निकलने दिया। लेकिन अब परीक्षा के लिए भेजना मजबूरी है। सरकार को परीक्षा जुलाई तक स्थगित कर देनी चाहिए। वहीं छात्र वैभव तिवारी का कहना कि परीक्षा के लिए वह मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। परीक्षा में पूरे तीन घंटे छात्रों के बीच बैठना है। यदि एक भी छात्र को कोरोना निकला तो सभी छात्र संक्रमित हो सकते हैं।

डिजिलेप अभियान से जुड़े हर स्टूडेंट, शिक्षक संवाद कर डिजिटल लर्निंग के लिए करें प्रेरित

संभागायुक्त ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की समीक्षा

सतना. कोरोना संकट के कारण संभाग के सभी स्कूलों में नियमित कक्षाएं बंद हैं। ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों को पढ़ाई का अवसर देने के लिए शासन ने डिजिटल लर्निंग इनहैन्समेंट प्रोग्राम (डिजिलेप) शुरू किया है। संभागायुक्त अशोक भार्गव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा की। अधिकारियों से कहा, कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण वर्तमान में शिक्षण संस्थान प्रारंभ नहीं किए जा सकते। इस कमी को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग ने डिजिलेप कार्यक्रम शुरू किया है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी डिजिलेप अभियान युद्ध स्तर पर चलाएं। कितनी भी कठिनाई व बाधाएं आएं पर अब विद्यार्थियों की पढ़ाई नहीं रुकेगी। उन्हें डिजिटल लर्निंग से पढ़ाई का अवसर मिलेगा। समीक्षा में सतना के अधिकारी भी शामिल हुए।

हर शिक्षक प्रतिदिन पांच अभिभावकों से करे संपर्क: बैठक में शामिल अधिकारियों को निर्देश देते हुए कमिश्नर ने कहा, 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को डिजिलेप अभियान से जोड़े। ताकि, उनकी पढ़ाई सतत जारी रह सके। इसके लिए विद्यार्थियों व अभिभावकों से संपर्क किया जाए। हर शिक्षक प्रतिदिन कम से कम पांच अभिभावकों से जरूर बात करे। विशेषकर उन अभिभावकों से जिनके पास वाट्सएप की सुविधा है, लेकिन ग्रुप से नहीं जुड़े। शिक्षक हर विद्यार्थी के पालक का फोन नंबर विद्यालय में मौजूद डाटाबेस से प्राप्त कर विद्यार्थी का टेलीफोन कॉल रजिस्टर बनाए। ताकि, विद्यार्थी को किए गए कॉल का विवरण दर्ज हो। सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर, दीवार लेखन व अन्य माध्यमों से डिजिलेप अभियान का प्रचार-प्रसार कराएं। प्रत्येक पंचायत में स्व सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कराएं।

समय-समय पर दें होमवर्क

प्रतिदिन शिक्षक कम से कम पांच विद्यार्थियों से संपर्क कर उन्हें शिक्षक भागीदारी फार्म में दर्ज करें। विद्यार्थियों को समय-समय पर होमवर्क देकर उन्हें ऑनलाइन पढ़ाई से जोड़े रखें। कोरोना वायरस की वजह से बच्चों की पढ़ाई किसी भी स्थिति में रुके नहीं, बच्चों के मन में किसी प्रकार भय न हो, इसके लिए उन्हें शासन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही ऑनलाइन रचनात्मक सामग्री से जोड़ने का प्रयास करें।

सुधार की आवश्यकता

संभागायुक्त ने कहा, रीवा संभाग में डिजिलेप अभियान में अत्यधिक सुधार की आवश्यकता है। सभी जिला शिक्षा अधिकारी, डाइट प्राचार्य व संकुल शिक्षक समय-समय पर ऑनलाइन बैठकें कर डिजिलेप के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों को दूर करें। जिला स्तर पर समय-समय पर वेबनार कर अभियान की समीक्षा करें। जिला स्तर पर ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से डिजिलेप अभियान के संबंध में विद्यार्थियों व उनके पालकों से सार्थक संवाद करें।

एजुकेशन सिस्टम में नए बदलावों पर पैरेंट्स और स्कूल मैनेजमेंट आमने सामने

ऑनलाइन एजुकेशन का बच्चों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ रहा बुरा प्रभाव, पैरेंट्स भी हो रहे परेशान

सीबीएसई : 137 सीबीएसई स्कूल हैं शहर में, **1000** से 1500 स्टूडेंट्स हैं हर स्कूल में **एमपी बोर्ड : 137** संकुल हैं एमपी बोर्ड के 9वीं से 12वीं तक के जिनमें 700 से 800 स्कूल आते हैं, **1600** स्कूल हैं कक्षा पहली से आठवीं तक।

पैरेंट्स की मांग

8वीं तक के बच्चों को इस साल मिले जनरल प्रमोशन

9वीं से 12वीं तक के बच्चों की सिर्फ ट्यूशन फीस ली जानी चाहिए

इंदौर. कोविड-19 ने हमारा जीवन जीने का अंदाज बदल दिया है और यह बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है। कोविड-19 के कारण शिक्षा जगत में ऑनलाइन एजुकेशन एक नई शिक्षा पद्धति के रूप में उभर कर आया है। ऑनलाइन एजुकेशन के कुछ लाभ हैं तो अभिभावकों के समक्ष कई चुनौतियां भी हैं। इस विषय में जब पत्रिका ने शहर के प्रमुख शिक्षाविदों से बात की उन्होंने इसके फायदे बताए लेकिन दूसरी ओर पालकों और कई संगठनों ने इसका विरोध किया और कहा कि ऑनलाइन एजुकेशन स्कूलों के लिए फीस वसूलने का साधन मात्र है।

स्कूलों का तर्क

पढ़ाई की लिंक छूट गई तो फिर से शुरू करने में होगी दिक्कत

टीचर्स की सैलेरी व खर्च निकालना हो रहा मुश्किल

फीस के लिए बच्चों पर बोझ डाल रहे स्कूल

गौरव चौधरी

एडवोकेट पेरेंट्स एसोसिएशन इंदौर

प्री-प्राइमरी, प्राइमरी और हाईस्कूल विंग के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन दिखावा मात्र है। यह सिर्फ फीस वसूलने का एक तरीका है। पिछले कुछ महीने जो कक्षाएं लगी हैं उसमें पांचवीं और छठवीं के बच्चों का सारा काम पैरेंट्स को करना पड़ा है। इससे वर्किंग पैरेंट्स के सामने चुनौतियां हैं क्योंकि घर, ऑफिस को मैनेज करने के साथ बच्चे की ऑनलाइन क्लास का भी हिस्सा बनना पड़ता है। इतने छोटे बच्चे कम्प्यूटर पर फोकस नहीं कर सकते। स्क्रीन पर छोटे बच्चों को कंट्रोल करना भी मुश्किल है। हर बच्चे पर फोकस संभव नहीं है। सारे स्कूल अभी बस और मेस का किराया काटकर पूरी फीस ले रहे हैं। स्कूलों द्वारा लाइब्रेरी फीस, स्पोर्ट्स फीस, कम्प्यूटर लैब फीस आदि को भी ट्यूशन फीस के रूप में लिया जा रहा है। इनकी कटौती नहीं की जा रही है।

फीस भरने के लिए दिए जाएं कई विकल्प

जितेंद्र पारवानी

संरक्षक इंदौर पालक संघ

कक्षा 9वीं तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन का कोई महत्व नहीं होता है क्योंकि उनके लिए कुछ भी नया सीखना ही एक चुनौती होता है। यह स्कूलों का फीस लेने का एक तरीका भर है। अभी जो बच्चे ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं उनके पैरेंट्स पूरे समय बच्चों के साथ में ही बिजी रहते हैं। वर्किंग पैरेंट्स के लिए तो दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। कई पैरेंट्स के पास स्कूल की तरफ से फीस भरने को लेकर मैसेज आ रहे हैं। स्कूलों को चाहिए कि वे पैरेंट्स को फीस भरने के लिए कई विकल्प दें। जैसे तीन माह की फीस को आने वाले तीन माह में एडजस्ट कर दिया जाए। कुछ पैरेंट्स की शिकायत यह भी है कि स्कूल अभी भी बढ़ा कर फीस ले रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सहायक है लेकिन उसमें भी फीस कम की जानी चाहिए।

हर ग्रेड के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सही

यू.के. झा

चेयरमैन इंदौर पब्लिक स्कूल

प्रमुख रूप से ऑनलाइन एजुकेशन की तीन चुनौतियां हैं। पहली जहां दो बच्चे हैं और ऑनलाइन क्लास का समय एक है तो उन्हें दो गैजेट्स की आवश्यकता के साथ पर्सनल स्पेस की आवश्यकता होगी। दूसरी इंटरनेट कनेक्टिविटी की समस्या और तीसरी छोटे बच्चों के साथ पैरेंट्स को बैठना पड़ता है। हालांकि बच्चों को टीचर के साथ बॉन्डिंग होती है तो वह उनसे सीखना ज्यादा पसंद करते हैं। हर ग्रेड के लिए ऑनलाइन एजुकेशन सही है। छोटे बच्चों के लिए क्लासेज इंटरेक्टिव हों। यदि क्लासेज को ब्रेक दिया तो उनके शेड्यूल में बदलाव होंगे साथ ही स्क्रीन पर भी ब्रेक लगेगा। फिर से शुरुआत करने में मेहनत लगेगी। गवर्नमेंट ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए गाइडलाइन जारी की है। स्कूलों के सामने टीचर्स और स्टाफ को सैलेरी देना भी एक चुनौती है।

सिर्फ सिलेबस पूरा कराने की कोशिश

डॉ. संगीता विनायक

प्रभारी प्राचार्य, शासकीय उत्कृष्ट बाल विकास केंद्र

निजी स्कूल, शासकीय स्कूल और सीबीएसई के बीच का बेस्ट है। एक निम्नवर्गीय परिवार बच्चों की शिक्षा के लिए निजी स्कूलों का चयन करता है। आज निजी स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन दी जा रही है और यदि ऐसा मान रहे हैं कि इससे बच्चों को पूर्ण शिक्षा दी जा सकती है तो यह भ्रम है। ऑनलाइन एजुकेशन से सिर्फ सतही ज्ञान ही हासिल किया जा सकता है। यह सिर्फ सिलेबस पूरा कराने का एक माध्यम होगा। ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों की क्षमताओं और मानसिक स्तर के साथ तालमेल संभव नहीं है। निम्न वर्गीय परिवारों में ऑनलाइन एजुकेशन के दृश्य भी उपलब्ध होना संभव नहीं है। फिलहाल ऑनलाइन एजुकेशन का लाभ सिर्फ 40 प्रतिशत स्टूडेंट्स ही ले पा रहे हैं क्योंकि इसकी कोई मॉनिटरिंग नहीं की जा रही है।

छोटे बच्चों को हो सकती है आंखों की समस्या

डॉ. योगेंद्र व्यास

नेत्र रोग विशेषज्ञ

छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइम यदि ज्यादा है तो उन्हें आंखों से संबंधित कई समस्या हो सकती है। ज्यादा देर तक स्क्रीन पर देखने से स्ट्रेस बढ़ता है। शार्ट लाइट आंखों को डेमेज करती है। इससे भेंगापन की समस्या भी बच्चों में हो सकती है। छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन एजुकेशन उचित नहीं है क्योंकि बच्चा उतना फोकस नहीं कर पाता है और आंखों को नुकसान होता ही है। इसके अलावा भी अगर देखें तो लंबे समय तक ऑनलाइन रहने के कई अन्य शारीरिक और मानसिक नुकसान भी हैं। छोटे बच्चों को ऑनलाइन एजुकेशन से बिल्कुल नहीं जोड़ना चाहिए, इसकी जगह उन्हें जनरल प्रमोशन दे देना चाहिए।

फिजिकली-मेंटली नकारात्मक असर हो सकता है

डॉ.अभय पालीवाल

पीडियाट्रिक सर्जन, सिर्फ मेंटल और साइकेट्री, एमजीएम

ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को लगातार स्क्रीन पर देखना होता है तो इसका फिजिकल और मेंटल दोनों असर बच्चों पर देखने को मिलता है। बच्चे कई बार चिड़चिड़ी हो जाते हैं। ऑनलाइन क्लास में बच्चा एक सिंगल रूम तक सीमित होकर रह जाता है ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो पाती है। अगर वह शारीरिक रूप से सक्रिय नहीं है तो मानसिक रूप से भी सक्रिय नहीं होगा। उसके लिए दोस्तों के साथ खेलना और गार्डन में एन्जॉय करना जैसी एक्टिविटीज का होना आवश्यक है। कई बार इस कारण बच्चों में नेगेटिव इमोशन डेवलप हो जाते हैं ऐसे में पैरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज के लिए मोटिवेट करें।

ऑनलाइन स्टडी ने बढ़ाई अभिभावकों की चिंता : लेपटॉप के साथ माता-पिता को भी बच्चों के साथ बैठना पड़ता है

ऑनलाइन क्लास बच्चों की, पर टेंशन पैरेंट्स को है

पत्रिका PLUS रिपोर्टर

भोपाल ◆ लॉकडाउन के बाद बच्चों को स्टडी से जोड़े रखने के लिए स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं। लेकिन पैरेंट्स के लिए ये टास्क काफी चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। पैरेंट्स का कहना है कि बच्चे किसी भी एज ग्रुप के हों, वे अभी ऑनलाइन क्लासेस को लेकर अभ्यस्त नहीं हुए हैं। ऐसे में उन्हें भी बच्चों के साथ बैठना पड़ता है। लॉकडाउन के बीच कई पैरेंट्स वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें एक ही समय में दोनों काम मैनेज करना पड़ रहे हैं। पैरेंट्स के अनुसार ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों को लगातार बैठाए रखना ही सबसे चुनौतीपूर्ण होता है। इस कारण उनका पूरा रूटीन ही चेंज हो गया है।

ये थे चैलेंजेस

वर्चुअल क्लासेस कभी भी क्लासरूम की जगह नहीं ले सकते। क्लासरूम में यदि बच्चों को लेक्चर के दौरान कोई प्रॉब्लम होती है तो वे तुरंत सवाल पूछ सकते हैं। वर्चुअल क्लास में ये सुविधा नहीं होती। क्लास के बाद बच्चों को अपने सवाल लिखकर देने पड़ते हैं। कई पैरेंट्स के पास लैपटॉप नहीं है। ऐसे में मोबाइल की स्क्रीन पर तीन-चार घंटे बच्चों का बैठना उनकी सेहत के लिए भी हानिकारक साबित हो रहा है। कई बच्चों को आंखों में जलन और सिरदर्द की शिकायत होने लगी है।

शुरुआत में एक घंटे की क्लास लगती थी, जो बाद में डेढ़ घंटे की हो गई। एक जून से चार पीरियड होंगे। मेरी बेटी निशिता क्लास-थर्ड में है। क्लास के दौरान पैरेन्ट्स से लेकर स्टूडेंट्स तक के मन में कई सवाल उठते हैं, लेकिन सवालों को क्लास के बाद लिखकर भेजना होता है। इसलिए बच्चों के मन में उस तरह का सेटिसफेक्शन लेवल नहीं होता। हालांकि ऑनलाइन क्लास में टीचर्स अपना बेस्ट देते हैं। इन दिनों सर्विंग बढ़ने से नेट की स्पीड काफी स्लो हो गई है, इसलिए कई बार साउंड और वीडियो क्वालिटी काफी खराब हो जाती है। मेरे पति गौतम भी बिजनेसमैन हैं, हम दोनों में से एक को अपना काम छोड़कर क्लास में बेटी के साथ बैठना होता है।

हर्षिता खेमचंदानी, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट

मेरी बेटी अविरा और अमायरा दोनों की ऑनलाइन क्लासेस चलती है। मैं और मेरे पति स्वप्निल दोनों वर्किंग हैं। दोनों स्कूल जाती थीं तो टीचर्स सीधे इंटरेक्ट करती थीं। फ्रेंड्स के बीच उन्हें भी अच्छा लगता था। अब डेढ़ घंटे की ऑनलाइन क्लासेस में उन्हें डेस्कटॉप के सामने बैठाए रखना ही चुनौतीपूर्ण होता है। पैरेन्ट्स के लिए बच्चों को पढ़ाना वैसे ही टफ टास्क होता है। बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो हम दोनों अपने कई काम निपटा लेते थे, अब पूरा शेड्यूल ही उनकी स्टडी के हिसाब से मैनेज करना पड़ता है।

नंदिनी गुप्ता, बिजनेस वुमन

बेटी भाव्या फोर्थ क्लास में है। हम ऑनलाइन क्लासेस के लिए तैयार नहीं थे। वेबकैम, की-बोर्ड, माउस व अन्य इंस्ट्रूमेंट की व्यवस्था की। बच्चे अभी ऑनलाइन क्लासेस के हिसाब से टेक्नो फ्रेंडली नहीं हुए। मोबाइल से नेट चलाते हैं, इसलिए नेटवर्क की समस्या है। अर्जेंट फोन कॉल्स आने पर क्लासेस में डिस्टर्बेंस आ जाता है। ऐसे में बच्चों के साथ हमें भी बैठना पड़ता है। ऑनलाइन असाइनमेंट व एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को पूरा कराना भी टफ होता है। बच्चे घर के माहौल को इतना सीरियस नहीं लेते।

अंकित-रोली जोशी, बिजनेसमैन

पति नीतेश सिंह बिजनेसमैन और मैं ब्यूटीशियन हूं। बेटी वंशिका छठी क्लास में है। हर पीरियड 45 मिनट का होता है। इसमें 15 से 20 मिनट का ब्रेक। लगातार क्लासेस से घर के कामों को मैनेज करना मुश्किल है, क्योंकि क्लास कभी सुबह 9.30 बजे से तो कभी 11.30 बजे से शुरू होती हैं। वर्क फ्रॉम होम के कारण नेटवर्क भी समस्या है। कभी अचानक नेटवर्क चले जाने से क्लास बीच में ही छूट जाती है। बच्चे समझ नहीं पाते कि टॉपिक कौन से बातें वे मिस कर गए।

सीमा सिंह, वर्किंग वुमन

विद्यार्थियों की आदत में शामिल नहीं हो पा रहा है ऑनलाइन क्लास का सिस्टम

इंदौर (नईदुनिया रिपोर्टर) लॉकडाउन में ज्यादातर शिक्षण संस्थानों ने ऑनलाइन क्लासेस तो शुरू कर दी है, लेकिन इनके इन्हें लम्बे समय तक चलाने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। पिछले एक से डेढ़ माह से विद्यार्थी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओर से अच्छे फीडबैक नहीं आ रहे। शिक्षण संस्थानों को विद्यार्थी कह रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई में उनका मन नहीं लग पा रहा है। वे कई चीजों को याद नहीं रख पा रहे हैं या ऑनलाइन लेक्चर के समय क्लास में पूरा ध्यान केंद्रित नहीं हो पा रहा है। इस परेशानी को फिलहाल शिक्षण संस्थानों के पास कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में विद्यार्थियों को कुछ सजेशन देकर ऑनलाइन क्लास में बने रहने के लिए कहा जा रहा है।

ऑनलाइन टेस्ट में भी विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे: शहर में इंजीनियरिंग और मेडिकल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने वाले एक कोचिंग संस्थान के प्रोफेसर का कहना है कि ऑनलाइन एजुकेशन की विद्यार्थियों को कभी आदत नहीं थी और अब अचानक सभी शिक्षण संस्थानों का फोकस इसे अपनाने का हो गया। विद्यार्थी इसके लिए कितने तैयार है इसका अंदाजा शुरुआत में तो नहीं लगा, लेकिन दो महीने की पढ़ाई के बाद विद्यार्थियों के निगेटिव फीडबैक से यहीं पता लग रहा है कि विद्यार्थियों में इसके इस्तेमाल को लेकर रूचि नहीं है। ऑनलाइन टेस्ट में भी इसका असर देखने को मिल रहा है। शिक्षाविद् प्रदीप श्रीवास्तव का कहना है कि कुछ दिन या महीनों की तैयारी के लिए ऑनलाइन सिस्टम को अपना सकते हैं, लेकिन रेगुलर पढ़ाई के लिए ऑनलाइन सिस्टम कभी भी स्थायी जगह नहीं बना सकता।

ऑनलाइन क्लास। ● सौजन्य इंटरनेट

सामान्य वीडियो की तरह हो रहे हैं शामिल

मनोचिकित्सक प्रियंका तिवारी का कहना है कि टीचर जब सामने होते हैं तो विद्यार्थी उनकी बातों को ज्यादा ध्यान से सुनते हैं। उनसे सवाल-जवाब भी कर लेते हैं, लेकिन इस समय ऑनलाइन लेक्चर में शामिल होना यूट्यूब के वीडियो देखने जैसा ही साबित हो रहा है। बच्चों में इसकी धीरे-धीरे आदत डालनी होगी।

इंटरनेट डेटा की कमी: आईटी एक्सपर्ट चेतन पुष्पद का कहना है कि लॉकडाउन के दौरान कई विद्यार्थी गांव चले गए हैं। ऐसे में उनके पास इंटरनेट डेटा सीमित होता है। वीडियो कांफ्रेंसिंग से होने वाली ऑनलाइन क्लास में काफी डेटा लग जाता है। सभी के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं होता है। ऐसे में भारत में ऑनलाइन क्लासेस को स्थापित होने में काफी समय लग जाएगा। कई विद्यार्थी मोबाइल से ऑनलाइन लेक्चर में शामिल हो रहे हैं, जिसमें उनकी रूचि नहीं होती।

लॉकडाउन असर ● उच्च शिक्षा विभाग ने एक दर्जन प्रस्ताव किए खारिज

न नए कॉलेज खुलेंगे, न नए पाठ्यक्रम

भोपाल (नईदुनिया प्रतिनिधि)। प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में नए निजी कॉलेज खोलने के लिए मिले सभी प्रस्ताव खारिज कर दिए हैं। विभाग को प्रदेश से करीब एक दर्जन निजी कॉलेज खोलने के प्रस्ताव मिले थे। अब इन कॉलेजों को मंजूरी के लिए अगले शैक्षणिक सत्र का इंतजार करना होगा। विभाग ने तय किया है कि इस साल न नए निजी कॉलेज खुलेंगे और न नए पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

दरअसल, नए कॉलेजों को मान्यता देने के पहले कमेटी उसका निरीक्षण करती है। यही प्रक्रिया नए पाठ्यक्रम शुरू करने के पहले अपनाई जाती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से यह संभव नहीं हो सका है। वहीं, पुराने कॉलेजों को बिना निरीक्षण के मान्यता दी जाएगी। कॉलेजों में इस साल सीटें भी नहीं बढ़ाई जाएंगी। कॉलेजों में पिछले साल जिन पाठ्यक्रम में जितनी सीटों पर प्रवेश देने की अनुमति थी। इस बार भी उतनी ही सीटों पर प्रवेश देने की अनुमति रहेगी। मान्यता का नवीनीकरण भी ऑनलाइन फीस जमा कराकर विभाग ने कर दिया है।

यह थी प्रक्रिया

हर साल उच्च शिक्षा विभाग मार्च-अप्रैल में नए कॉलेज और पाठ्यक्रम संचालित करने और सीटों में बढ़ोतरी के लिए आवेदन मंगाता था। इस साल से यह प्रक्रिया ऑनलाइन की गई थी। आवेदनों के आधार पर विभाग कमेटी बनाकर उस कॉलेज के भौतिक निरीक्षण के लिए कमेटी के सदस्यों को भेजता था। निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर मान्यता दी जाती थी। इस बार लॉकडाउन की वजह से न कमेटी का गठन हो सका और न कॉलेजों का निरीक्षण हुआ। यही प्रक्रिया नए पाठ्यक्रम शुरू करने और सीटों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए अपनाई जाती थी। अब विभाग यदि कमेटी बनाकर निरीक्षण कराता है तो पूरी प्रक्रिया में तीन से चार महीने लग जाते। इससे न सिर्फ कॉलेज देर से शुरू होते बल्कि अन्य कार्य भी प्रभावित होता। इन परिस्थितियों में विभाग ने नए निजी कॉलेजों की मान्यता और नए पाठ्यक्रम के संबंध में यह फैसले लिए हैं।

हबीबगंज से चलेंगी शान-ए-भोपाल व जनशताब्दी

भोपाल (नप्र)। लॉकडाउन के बाद सोमवार से ट्रेनों की संख्या बढ़ जाएगी। हबीबगंज से शाम को 5.40 बजे पहली ट्रेन जनशताब्दी एक्सप्रेस चलेगी। यह इटारसी के रास्ते जबलपुर जाएगी। हबीबगंज स्टेशन से ही रात 9.05 बजे शान-ए-भोपाल एक्सप्रेस चलेगी। यह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन जाएगी। ये ट्रेनें प्रतिदिन चलेंगी और हबीबगंज स्टेशन पर आकर इनका सफर पूरा होगा। इनका मेंटेनेंस भी हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर किया जाएगा। रविवार शाम को दोनों ट्रेनों के कोच की धुलाई कर दी गई। उसके बाद इसे सैनिटाइज किया गया।

कठिन पढ़ाई के साथ स्टूडेंट्स के समग्र विकास पर आधारित है चीन की शिक्षा

चीन के स्कूलों में बच्चों के लिए रिलेक्सेशन पीरियड

चीन के पढ़ाई करने के तरीकों को दुनिया में पढ़ाई के बेस्ट तरीकों में शामिल किया गया है। यहां के स्कूलों में बच्चों पर पढ़ाई का बोझ नहीं लादा जाता, बल्कि उन्हें इस तरह से शिक्षा दी जाती है कि वे थका हुआ महसूस न करें। इसके लिए चीन के स्कूलों में बीच-बीच में बच्चों को रिलेक्सेशन भी कराया जाता है।

ZOOM रिपोर्टर
patrika.com

चीन के स्कूलों में बच्चे दिन भर में दो बार वार्म अप करते हैं। चीन में तीसरे पीरियड के बाद बच्चे अपनी आंखों को रिलेक्स करने के लिए आई एक्सरसाइज भी करते हैं और पढ़ाई के दौरान अपनी बॉडी को आराम देने के लिए एक्युप्रेशर भी करते हैं।

स्टूडेंट्स के लिए यहां पर म्यूजिक क्लास भी लगाई जाती है, जिसमें वे तनाव को दूर करने के लिए संगीत उपकरण बजाते हैं, डांस करते हैं। बच्चों को खाना खाने के लिए एक घंटे का टाइम दिया जाता है और कुछ स्कूलों में बच्चों को बीच में सोने की भी इजाजत दी जाती है। तनाव दूर करने और शरीर को रिलेक्स करने के स्कूल टाइम के दौरान स्टूडेंट्स थोड़ी देर नींद ले सकते हैं।

प्राथमिक शिक्षा को महत्व

चीन का मानना है कि अगर देश को भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो बच्चों को प्राथमिक स्तर पर अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। चीन में प्री-स्कूल एजुकेशन को बहुत महत्व दिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रि-स्कूलों में बच्चों को शिक्षित किया जाता है, तो शहरी क्षेत्रों मे प्रि-स्कूल एजुकेशन किंडरगार्डन के जरिए मिलती हैं। इसके बाद चीन में विधिवत पढ़ाई की शुरुआत 6 साल की उम्र से होती है और बच्चे ग्रेड 1 में 6 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू करते हैं।

पढ़ाई का स्तर बेहद कठिन

चीन में पढ़ाई काफी कठिन हैं। कॉलेज में एडमिशन सेकेंडरी के नंबर के आधार पर मिलता है। वहीं स्कूलों में स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ ही नेशनल हायर एजुकेशन के लिए होने वाले एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी भी कराई जाती है। गायको नाम का यह एंट्रेंस एग्जाम बहुत कठिन होता है और इसके नंबर के आधार पर एडमिशन हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में होता है। गायको नौ घंटे का एग्जाम होता है और यह इतना कठिन है कि सिर्फ 40 फीसदी स्टूडेंट्स इसे पास कर सकते हैं। इसे पास करने वाले स्टूडेंट्स को चाईनीज यूनिवर्सिटी में दाखिला मिलता है।

मंडल ने शुरू की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी

क्वारंटीन सेंटर होने के कारण जिले का एक परीक्षा केन्द्र बदलेगा

क्वारंटीन सेंटर बनाए गए 28 परीक्षा केंद्रों को कराया गया खाली, परीक्षा के पहले होगा सेनीटाइज

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

सतना. माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शेष बची बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी प्रारंभ कर दी है। इसके तहत निर्णय लिया गया है कि अगर कोई परीक्षा केंद्र कंटेनमेंट जोन में निर्धारित है। अथवा किसी परीक्षा केंद्र को अगर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है तो ऐसे केंद्र को परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। इस संबंध में मंडल ने जानकारी तलब करनी शुरू कर दी है। सतना जिले में इस मापदण्ड में एक परीक्षा केंद्र आता है, जिसे बदलने का प्रस्ताव मंडल को भेजा जाएगा।

मिली जानकारी के अनुसार, सतना जिले के 29 परीक्षा केंद्र ऐसे थे, जहां बाहर से आने वाले प्रवासियों को रोकने के लिए क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था। लेकिन हाल में ली गई जानकारी के अनुसार 28 विद्यालयों में अब कोई भी व्यक्ति क्वारंटीन नहीं है। अगर किसी में इक्का दुक्का लोग बचे भी थे वे खाली करके जा चुके हैं। ऐसे में अब इन विद्यालयों में वापस परीक्षा केंद्र के रूप में उपयोग में लिया जा सकेगा। लेकिन नागौद का उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जिले में इकलौता ऐसा केंद्र बचा है, जो अभी भी क्वारंटीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में इस परीक्षा केंद्र को बदलना पड़ेगा। इसकी तैयारी और रूपरेखा डीईओ कार्यालय ने तैयार कर ली है। बताया जा रहा है कि इसके स्थान पर स्थानीय निजी विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाएगा।

28 विद्यालय किए जाएंगे सेनीटाइज

जिला शिक्षाधिकारी टीपी सिंह ने बताया कि जो 28 विद्यालय क्वारंटीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किए गए थे और उन्हें खाली करा लिया गया है। परीक्षा के पहले उन्हें पूरी तरह से सेनीटाइज किया जाएगा। पूरी साफ सफाई के बाद यहां परीक्षा कक्ष की पूरी तरह से साबुन से धुलाई करने के बाद इसे अलग से सेनीटाइज भी किया जाएगा।

इन विद्यालयों का विकल्प क्या

हालांकि, डीईओ कार्यालय से यह तो स्पष्ट हो गया है कि 28 विद्यालय क्वारंटीन सेंटर से हटा लिए गए हैं। लेकिन वर्तमान स्थिति में इनका विकल्प क्या रखा गया है इस पर अभी कोई स्पष्ट जानकारी किसी जिम्मेदार की ओर से नहीं मिल पा रही है। यह जरूर बताया जा रहा है कि संबंधित क्षेत्र के किसी अन्य शासकीय भवन को क्वारंटीन सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

ऊंची उड़ान 5 लाख से ज्यादा हैं इनके सब्सक्राइबर

पहली फीमेल यूट्यूबर जो सैकड़ों स्टूडेंट्स को एक क्लिक में करवा रहीं कॉम्पीटेटिव एग्जाम की तैयारी

प्रिया जैन को बचपन से ही कुछ नया सीखना और ट्राई करना पसंद था। जुलाई 2018 में यूट्यूब के जरिए नॉलेज देना शुरू किया और रोजाना उनके सब्सक्राइबर बढ़ते जा रहे हैं।

ZOOM रिपोर्टर
patrika.com

ये कहानी है रायपुर की प्रिया जैन की। मैट्स यूनिवर्सिटी से लॉ में ग्रेजुएशन के बाद नालसर यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मास्टर किया। उसी शहर में सिम्बायोसिस लॉ स्कूल हैदराबाद में पढ़ाना शुरू किया। टीचिंग में शुरू से इंट्रेस्ट रहा। छुट्टियों में घर आई तो यहां एक टर्निंग प्वाइंट आया। सोच थी कि कॉम्पीटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को आईपीसी की धाराओं के बारे में बताना। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और उससे जुड़े प्रावधान को इस तरीके से बताना कि झट से याद हो जाए। हालांकि इतनी बड़ी कामयाबी का सोचा नहीं था लेकिन आज फिनोलॉजी लीगल के 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर इस बात के गवाह हैं कि प्रिया का नॉलेज उनके बहुत काम का है।

फैमिली में पहला लॉ बैकग्राउंड

मेरी फैमिली में बहुत सारे लोग डॉक्टर, इंजीनियर और सीए हैं पर लॉ बैकग्राउंड वाली मैं पहली मेंबर हूं। ज्यादातर लोग जब किसी यूट्यूबर्स या वीडियो को देखते हैं तो उनको लगता है कि ये तो बड़ा आसान काम होगा लेकिन आप किसी छात्र को ऑनलाइन कोई नई चीज सिखाते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है।

हजार सीढ़ियों के लिए पहली सीढ़ी

मुझे आज भी वो दिन याद है जब मैं मोबाइल और ट्राइपॉड से वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी। रिकॉर्डिंग से लेकर एडिट, सबटाइटल और ग्राफिक, अपलोड सारा काम खुद किया करती थी। आर्टिकल और संविधान से जुड़ा मेरा पहला वीडियो 100 लोगों ने देखा तो मैं काफी उत्साहित हुई। मैंने पढ़ा था कि हजार सीढ़ियां चढ़ने के लिए पहली सीढ़ी पर कदम रखना होता है। ये मेरा पहला कदम था। 377, ट्रिपल तलाक, अयोध्या पर मेरे वीडियो काफी हिट हुए। पिछला डेढ़ साल मेरे चैनल के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ।